उत्तर प्रदेश शासन द्वारा विज्ञापन मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र

सच का साथी..

बी पी एस न्यूज

www.bpsnews.in

(वर्ष-9 अंक-26)

पृष्ठ 8 मूल्य 2/रुपया

सोमवार 29 जुलाई, 2024

विधायक ने सिंचाई विभाग के एई को बुलडोजर की नोटिस पर लिया आड़े हाथों 8

बेटी की बरामदगी के लिए भटक रही मां 6

भारत को 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने पर जोर

पीएम मोदी ने बैठक में एजेंडे पर की विस्तार से चर्चा

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें अधिक मजबूती से लोक कल्याण के समन्वित और मजबूत प्रयासों में जुट जाती हैं तो 'विकसित भारत' का लक्ष्य निश्चित तौर से हासिल किया जा सकता है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सुशासन प्रकोष्ठ के संयोजक विनय सहस्त्रबुद्धे की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक मोदी ने कहा कि विरासत का विकास करना और विकास की विरासत का निर्माण करना 'विकसित भारत' की संकल्पना में विशेष महत्व रखता है। प्रधानमंत्री यहां भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) शासित राज्यों के 13 मुख्यमंत्रियों और 15 उपमुख्यमंत्रियों की दो दिवसीय बैठक के दूसरे दिन उन्हें संबोधित कर रहे थे।मोदी ने देश को 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के अपनी सरकार के एजेंडे के बारे में विस्तार से चर्चा की और कल्याणकारी उपायों में जनता की भागीदारी के महत्व पर जोर दिया। सहस्त्रबुद्धे ने कहा कि प्रधानमंत्री ने विभिन्न समूहों को लक्षित करते हुए सरकारी योजनाओं की अधिकतम पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर भी जोर दिया। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह और जे पी नड्डा सहित वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने मुख्यमंत्री परिषद में भाग लिया। इसका आयोजन समय-समय पर होता रहता है और इसमें बड़े पैमाने पर शासन के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई शिक्षा नीति और इसके क्रियान्वयन में राज्यों की भूमिका के बारे में बात की। बैठक के दौरान विभिन्न राज्यों ने अपनी कुछ प्रमुख व महत्वाकांक्षी योजनाओं पर प्रस्तुति दी। मुख्यमंत्रियों समेत भाजपा नेताओं के साथ बातचीत में मोदी ने अक्सर कल्याणकारी योजनाओं की कवरेज सुनिश्चित करने की जरूरत पर जोर दिया है और कहा है कि पार्टी शासित राज्यों को सुशासन के उदाहरण के तौर पर देखा जाना चाहिए। उन्होंने शनिवार को कहा, %हमारी पार्टी सुशासन को आगे बढ़ाने और लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अथक प्रयास कर रही है। भाजपा द्वारा नियमित अंतराल पर आयोजित मुख्यमंत्री परिषद का उद्देश्य राज्यों में प्रमुख योजनाओं की समीक्षा करना, शासन के सर्वोत्तम तौर-तरीकों और केंद्र सरकार की कल्याणकारी पहल को लागू करना है। बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा, राजस्थान के भजनलाल शर्मा और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी शामिल हुए। मध्यप्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, हरियाणा, मणिपुर और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों ने भी विचार-विमर्श में हिस्सा लिया।

आईएएस कोचिंग त्रासदी

असुरक्षित निर्माण की कीमत लोग जान गंवाकर चुका रहे : राहुल गांधी

नई दिल्ली। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में एक कोचिंग संस्थान की इमारत के 'बेसमेंट' में पानी भरने के कारण सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे तीन अभ्यार्थियों की मौत पर रविवार को शोक जताया। राहुल गांधी ने कहा कि आम लोग असुरक्षित निर्माण, खराब नगर नियोजन और हर स्तर पर संस्थानों के गैर-जिम्मेदाराना रुख की कीमत अपनी जान गंवाकर चुका रहे हैं।

कांग्रेस नेता ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, दिल्ली की एक इमारत के 'बेसमेंट' में पानी भर जाने के कारण प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे तीन अभ्यर्थियों की मौत बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कुछ दिन पहले बारिश के दौरान करंट लगने से एक अभ्यर्थी की मौत हो गई थी। सभी शोकाकुल परिजनों के प्रति भावपूर्ण संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। उन्होंने कहा, इस तरह का असुरक्षित निर्माण तंत्र की साझा असफलता है। असुरक्षित निर्माण, लचर नगर नियोजन और हर स्तर पर संस्थाओं के गैर-जिम्मेदाराना रुख की कीमत आम नागरिक अपना जीवन गंवाकर चुका रहे हैं। दिल्ली की एक बिल्डिंग के बेसमेंट में पानी भर जाने के कारण प्रतियोगी छात्रों की मृत्यु बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कुछ दिन पहले बारिश के दौरान बिजली का करंट लगने से एक छात्र की मृत्यु हुई थी।गांधी ने कहा कि एक सुरक्षित एवं आरामदायक जीवन हर नागरिक का अधिकार है और इसे सुनिश्चित करना सरकारों का दायित्व है। दिल्ली पुलिस ने रविवार को उस कोचिंग सेंटर के मालिक और समन्वयक को गिरफ्तार कर लिया, जिसके 'बेसमेंट' में शनिवार को पानी भर जाने के कारण तीन अभ्यर्थियों की मौत हो गई। ?अधिकारियों ने बताया कि पुलिस ने उनके खिलाफ गैर-इरादतन हत्या समेत अन्य आरोपों के तहत मामला दर्ज किया है।

राजेंद्र नगर हादसे को लेकर दिल्ली की आप सरकार पर भड़कीं स्वाति मालीवाल

परिजनों के लिए की मुआवजे की मांग

नई दिल्ली। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल रविवार को ओल्ड राजेंद्र नगर पहुंचीं, जहां शनिवार शाम को एक बड़ा हादसा हुआ। इस दौरान मालीवाल ने उन छात्रों से भी मुलाकात की, जो घटना में जान गवाने वाले तीन छात्रों की मौत के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन कर रहे थे। मालीवाल ने घटनास्थल पर दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के किसी भी मंत्री के नहीं आने पर सवाल उठाए। इस दौरान उन्होंने घटना में जान गवाने वाले छात्रों की मौत को हत्या करार दिया और उनके परिवार वालों के लिए मुआवजे की मांग भी की।मालीवाल ने आप सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, बच्चे बहुत दुःखी हैं और बहुत गुस्से में हैं। 12 घंटे से ज्यादा हो गए हैं लेकिन अभी तक न दिल्ली सरकार के कोई मंत्री या दिल्ली की मेयर आई हैं, कोई अधिकारी नहीं आया है। इन बच्चों को अपने हाल पर छोड़ दिया गया है। छात्रों की मौत को हत्या करार देते हुए राज्यसभा सांसद ने दिल्ली सरकार के मंत्रियो के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। उन्होंने कहा, मैं मानती हूं कि ये मौत कोई आपदा नहीं है बल्कि ये हत्या है, जितने भी दिल्ली सरकार के बड़े-बड़े लोग हैं उन पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए।

श्रीलंकाई महिला टीम ने भारत से छीना चैंपियन का ताज, पहली बार बनी एशिया की चैंपियन

नई दिल्ली। भारत विमेंस एशिया कप की सबसे सफल टीम है। अब तक महिला एशिया कप के 9 सीजन हो चुके हैं, जिससे से भारतीय टीम 7 बार चैंपियन रही है। पिछली बार 2022 में विमेंस एशिया कप खेला गया था। तब भारत ने फाइनल मुकाबले में श्रीलंका को हराकर ट्रॉफी अपने नाम की थी।

श्रीलंकाई महिला टीम ने अपने घर में खेले गए महिला एशिया कप 2024 टूर्नामेंट में इतिहास रच दिया है। फाइनल मुकाबला रविवार को दांबुला में खेला गया। जिसमें श्रीलंका ने भारतीय महिला टीम को 8 विकेट से हराकर पहली बार खिताब जीत लिया है। बता दें कि, भारत विमेंस एशिया कप की सबसे सफल टीम है। अब तक महिला एशिया कप के 9 सीजन हो चुके हैं, जिससे से भारतीय टीम 7 बार चैंपियन रही है। पिछली बार 2022 में विमेंस एशिया कप खेला गया था। तब भारत ने फाइनल मुकाबले में श्रीलंका को हराकर ट्रॉफी अपने नाम की थी। महिला एशिया कप के पिछले 8 सीजन में से एक ही बार बांग्लादेश ने 2018 सीजन अपने नाम किया था। 7 बार भारत जीता था। लेकिन ये 9वां सीजन श्रीलंकाई टीम ने जीतकर इतिहास रच दिया है। दूसरी ओर पाकिस्तान टीम अब तक कोई भी महिला एशिया कप खिलाब नहीं जीत सकी। इस हार के साथ ही भारतीय टीम ने दूसरी बार महिला एशिया कप का फाइनल मैच गंवाया है। भारतीय टीम सभी 9 सीजन के फाइनल में पहुंची है।

विज्ञापन कार्यालय-130/4 - बाबू पुरवा कॉलोनी, किदवई नगर, कानपुर

नवीन गुप्ता (विज्ञापन प्रतिनिधि)

बीपीएस न्यूज समाचार पत्र व ऑनलाइन न्यूज चैनल (पोर्टल) में विज्ञापन लगवाने के लिए संपर्क करें। मो. 9839625941

बी पी एस न्यूज परिवार की ओर से सभी देशवासियों को

श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं

सम्पादक (बी.पी.साहू)
मो.8423454502,9335908846

बी पी एस न्यूज लेटेस्ट खबरें पढ़ने व देखने के लिए लॉगिन करें
www.bpsnews.in

दीपावली व छठ पूजा की
NEW SAHU FAMILY RESTAURANT
638y-1, Block Kidwai Nagar
Near -Dasu Kunwa Chauraha Noubasta Kanpur
Suresh Sahu
M.-8303637506, 9792526852
Web .site—www.sahufamilyrestaurant.com

Jai Ambey Traders

संपादकीय

केन्द्र को झटका

आखिरकार केंद्र और राज्यों के बीच अधिकारों की कानूनी लड़ाई तार्किक परिणति तक पहुंच ही गई है। देश की शीर्ष अदालत ने फैसला सुनाया है कि किसी भी राज्य के खनिजों पर देय रॉयल्टी एक कर नहीं है। साथ ही स्पष्ट किया कि राज्यों के पास खानों, खनिजों और खनिज-युक्त भूमि पर कर लगाने की विधायी क्षमता निर्धारित है। दरअसल, इस सारे विवाद के मूल में खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 रहा है। इस अधिनियम का हवाला देते हुए केंद्र सरकार की दलील थी कि केवल संसद ही खनिजों पर कर लगा सकती है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट की बैंच ने इस बाबत फैसला सुनाया कि कानून राज्यों को खानों और खनिज विकास पर कर लगाने से प्रतिबंधित नहीं करता है। निश्चित रूप से इस फैसले से प्राकृतिक संपदा से संपन्न गरीब राज्यों मसलन झारखंड और ओडिशा को विशेष रूप से लाभ होने की उम्मीद जगी है। ये राज्य केंद्र द्वारा खानों और खनिजों पर लगाये गए हजारों करोड़ों रुपये के करों की वसूली की मांग करते रहे हैं। निस्संदेह, यदि केंद्र सरकार राज्यों की माली हालत के मद्देनजर उनकी जरूरतों तथा आकांक्षाओं के प्रति संवेदनशील होती तो निश्चित रूप से इस विवाद को बातचीत के जरिये सुलझाया भी जा सकता था। जब लंबे समय तक इस मामले का निस्तारण नहीं हो सका तो अन्ततः देश की शीर्ष अदालत को गतिरोध तोड़ने के लिये हस्तक्षेप करना ही पड़ा। इसमें दो राय नहीं है कि केंद्र और राज्यों के बीच कई मुद्दों पर टकराव कोई नई बात नहीं है। लेकिन देखने में आया है कि हाल के वर्षों में यह विवाद आम बात हो चला है। निश्चित रूप से किसी भी राष्ट्र की संघीय व्यवस्था के लिये ये टकराव व विवाद कोई शुभ संकेत तो कदापि नहीं हैं। इसमें दो राय नहीं कि कुछ मुद्दे सहमति, सामंजस्य और संवेदनशीलता से भी सुलझाए जा सकते हैं। जिससे राज्यों के आर्थिक संकट को भी दूर किया जा सकता है।दरअसल, इस बात पर गंभीर विमर्श की जरूरत है कि हाल के वर्षों में केंद्र-राज्यों के बीच कलह के मामले लगातार क्यों बढ़ते जा रहे हैं। निस्संदेह, इस टकराव के राजनीतिक निहितार्थ भी हैं। इस विवाद को हाल में संसद में प्रस्तुत आम बजट के परिप्रेक्ष्य में भी देखा जा सकता है। यही वजह है कि वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट में राजग गठबंधन में शामिल बिहार तथा आंध्र प्रदेश के लिये घोषित विशेष पैकेजों ने विपक्ष को गैर भाजपा शासित राज्यों से कथित भेदभाव के आक्षेपों के साथ सवाल उठाने का मौका दिया है। विपक्ष ने केंद्र सरकार पर राजनीतिक रूप से पक्षपात वाला बजट बनाने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं कई विपक्षी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने बजट में भेदभाव का आरोप लगाते हुए आगामी 27 जुलाई को होने वाली नीति आयोग की बैठक में शामिल न होने की बात कही है। जो कि केंद्र व राज्यों के बीच टकराव की अप्रिय स्थिति को ही दर्शाता है। यदि अतीत के पन्ने पलटें तो वर्ष 1980 के दशक के उत्तरार्ध में, सरकारिया आयोग ने सहकारी संघवाद के सिद्धांतों के आधार पर सामंजस्यपूर्ण संघ-राज्य संबंधों की जरूरत पर बल दिया था।

दीर्घकालीन लक्ष्य होते हैं आदर्श बजट के

विद्रूपता यह कि सबसे गरीब तबका, जिसे यूं तो आयकर नहीं देना पड़ता, तथापि अपने उपभोग की तमाम उन वस्तुओं पर वह कर चुकाता है, जो जीएसटी तंत्र के तहत आती हैं। केंद्र एवं राज्य सरकारों को जीएसटी से जुड़े विषयों में सुधार और अधिक किए जाने की जरूरत है, हालांकि इन पर सर्वसम्मति पाना सदा कठिन रहा है। इसके अलावा, यह भी गलत है कि सेस से होने वाली कमाई अकेले केंद्र के हिस्से आए, जिसे वह आगे राज्यों से बांटना नहीं चाहता। उगाहे गए कराधान की जरूरत सूबों को भी उतनी है ताकि वे अपने विकास ध्येयों को पूरा कर पाएं। मसलन, गरीब छात्रों के लिए शिक्षा सुनिश्चित करना।

हर साल केंद्रीय सरकार पहले आर्थिक सर्वे और फिर बजट प्रस्तुत करती है। सर्वे के जरिये बताया जाता है कि अर्थव्यवस्था की हालत क्या है और बज़ट के माध्यम से अपनी सोची कार्ययोजना पेश करती है। इनको दो विचारों के मद्देनज़र देखा जाता है ~मौजूदा परिस्थिति के परिप्रेक्ष्य में क्या किया जाना चाहिए? और क्या चीज़ें सही दिशा में जाने वाली हैं?किंतु लगता है सरकार इतने में खुश है कि पिछले 10 सालों की सत्ता के दौरान उसकी उपलब्धि क्या रही। वित्तीय वर्ष -2023-24 में आर्थिक वृद्धि दर 8.2 फीसदी रही, इस तरह भारत दुनियाभर की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ती आर्थिकी बना, जबकि वर्ष 2023 में वैश्विक आर्थिक वृद्धि दर 3.2 प्रतिशत रही। भारत को इस बात पर यकीन है 2024-25 में मुद्रास्फीति 4.5 फीसदी के अंदर रख पाएगा। लेकिन यह दृश्यावली इतनी भी गुलाबी नहीं है। वर्ष 2023-24 के बीच खुदरा महंगाई दर 5.4 प्रतिशत रही। इससे भी अधिक चिंताजनक यह कि खाद्य महंगाई दर 7.5 प्रतिशत जितनी ऊंची रही।कुल मिलाकर, इस क्षेत्र में कारगुजारी बेहतर रहने के साथ, आर्थिक सर्वे में 2047 तक 'विकसित भारत' बनाने के ध्येय की पूर्ति हेतु अगले सालों में वृद्धि दर पाने की रणनीति के बारे में बताया गया है। वृद्धि निरंतर बनी रहे इसके लिए निजी क्षेत्र को अपनी पूंजी तलाशनी होगी। भारत को हरित ऊर्जा राष्ट्र में तबदील करने के लिए सार्वजनिक-निजी साझेदारी को बढ़ावा देना होगा। सरकार को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग तंत्र में खामियों को दूर करना होगा ताकि उनकी तरक्की होती रहे। नीतियों को अमलीजामा पहनाने के लिए राजकीय मशीनरी और व्यवस्था के लिए अपनी कामकाजी गति बढ़ाना जरूरी है। यदि यह अगले 25 सालों का दीर्घकालीन ध्येय है तो इसकी शुरुआत अब हम कहां से करें? प्रथम, करदाताओं के लिए अच्छी खबर यह है कि मानक कर कटौती (स्टैंडर्ड टैक्स डिडक्शन) को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया गया है। टैक्स स्लैब में कुछ बदलाव किया गया है ताकि नौकरीपेशा लोगों के हाथ में 17,000 रुपये तक बचत हो पाए। व्यावसायिक लोग कार्यबल का हिस्सा बनें, इसके लिए उन्हें प्रोत्साहन पैकेज मिलेगा। इससे 20 लाख से अधिक युवाओं को फायदा होने की उम्मीद है। न केवल वेतन पाने वालों को बल्कि पूंजी निवेश से लाभ कमाने वालों को भी आमदनी कर में छूट देकर राहत दी गई है।इस प्रकार, यह बजट मध्य वर्ग का मददगार है, क्योंकि उन्हें कर कम चुकाना पड़ेगा। विद्रूपता यह कि सबसे गरीब तबका, जिसे यूं तो आयकर नहीं देना पड़ता, तथापि अपने उपभोग की तमाम उन वस्तुओं पर वह कर चुकाता है, जो जीएसटी तंत्र के तहत आती हैं। केंद्र एवं राज्य सरकारों को जीएसटी से जुड़े विषयों में सुधार और अधिक किए जाने की जरूरत है, हालांकि इन पर सर्वसम्मति पाना सदा कठिन रहा है। इसके अलावा, यह भी गलत है कि सेस से होने वाली कमाई अकेले केंद्र के हिस्से आए, जिसे वह आगे राज्यों से बांटना नहीं चाहता। उगाहे गए कराधान की जरूरत सूबों को भी उतनी है ताकि वे अपने विकास ध्येयों को पूरा कर पाएं। मसलन, गरीब छात्रों के लिए शिक्षा सुनिश्चित करना।

बज़ट में भाजपा के सहयोगी दल, जैसे कि नीतीश कुमार के जद यू और चंद्रबाबू नायडू की तेलुगू देसम पार्टी को खुश करने के लिए कई बड़ी परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। भाजपा, जिसके पास अपने बूते सरकार बनाने का पूर्ण बहुमत नहीं है, हर हीले-हवाले से केंद्र में अपनी सत्ता कायम रखना चाहेगी। स्वीकृत मुख्य परियोजनाओं में, पटना-पूर्णिया और बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेस-वे के अतिरिक्त बिहार के बक्सर जिले में गंगा नदी पर दो लेन वाला पुल बनना है। इसके अलावा, भागलपुर के पीरपैंती में 2400 मेगावाट क्षमता वाला बिजलीघर बनेगा। आंध्र प्रदेश के लिए रेल एवं सड़क मार्ग परियोजनाएं घोषित की गई हैं, इसकी नई बनने वाली राजधानी के लिए 15,000 करोड़ रुपये देना घोषित किया गया है।इस बजट, जो कि राजनीति साधने का उपाय अधिक है, का ध्येय साफ है—यह सुनिश्चित करना कि भाजपा के मुख्य सहयोगी दल- जिनकी बैसाखी के बिना भाजपा सत्ता में नहीं टिक पाएगी- और मध्य वर्ग संतुष्ट रहे। मध्य वर्ग को खुश करने के पीछे मुख्य वजह भाजपा पर हावी व्यापारी वर्ग का धंधा चलाए रखने के आरोप से मुक्ति क्योंकि, यदि चुनावी आंकड़ों के लिहाज से देखा जाए तो छोटे वोट बैंक के तौर पर मध्य वर्ग की हैसियत नहीं है कि चुनाव परिणामों पर फर्क डाल सके। सत्ताधारियों का मनोरथ सदा अपने लोगों को खुश रखना होता है।तात्कालिक में, सरकार के लिए चीज़ें अच्छी नहीं हैं। बेशक दुनियाभर के आर्थिक टीकाकार भारत की उच्च वृद्धि दर की वाहवाही करें, लेकिन यह वृद्धि लगातार बनी रहे, इसके लिए कार्यबल का निरंतर बेहतर कौशल से लैस होते रहना और उसका स्वास्थ्य बढ़िया रहना नितांत जरूरी है। लेकिन मौजूदा बजट में इन महत्वपूर्ण विषयों के लिए नए कार्यक्रम केवल नाम भर के हैं। इसलिए कुल मिलाकर महसूस यह हो रहा है कि भले ही सत्ताधारी दल को अपनी राजनीतिक प्राथमिकताओं की तो समझ पूरी है, लेकिन नज़रिया दूरदर्शी नहीं है।बजट से उम्मीदें उन मुद्दों को भी रेखांकित करने की थी जो वक्त की जरूरत है, चाहे जमीनी हकीकत कुछ भी हो। आर्थिक वृद्धि दर की ऊपर उठती रेखा के बावजूद, वस्तुओं की बाजार मांग कमजोर है, रोजगार के मौके गंभीर रूप से बहुत कम हैं। क्या उच्च आर्थिक वृद्धि का फल अधिकांश लोगों को मिल रहा है? और यह बिंदु कुछ तकनीकी है-क्या मुद्रास्फीति दर कम बताने वाली गणना वाकई सही है?इस पर बहुत से लोगों की दलील है कि वृद्धि दर उतनी नहीं है जितनी बताई जाती है, क्योंकि नोटबंदी और कोविड-19 महामारी के कारण अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हुआ। इसलिए, एक प्रकार से, यह खुद को दुबारा स्थापित करने की कोशिश है। वस्तुओं की मांग इसलिए नहीं है कि लोग अधिक बचत करने में लगे हैं बल्कि वे अपनी खपत इसलिए कम कर रहे हैं ताकि वह ऋण उतारा जा सके जो उन्होंने नोटबंदी और महामारी में आमदनी न रहने पर उठाया था। खुदरा महंगाई दर इसलिए काबू में नहीं है कि आपूर्ति बहुतायत में है वरन? इसलिए है कि लोग वह खरीद नहीं पा रहे, जो वो चाहते हैं।फिर यहां एक बहुत बड़ा विरोधाभास भी है। यदि आर्थिकी और व्यापार लगातार बढ़िया कर रहा है, तब रिज़र्व बैंक के लिए ऋण दर कम रखना लाजिमी हो जाता। लेकिन फिर, बैंक पैसा जमा करवाने वालों को और लुभाने के लिए बचत खाते पर उच्च दर से ब्याज कैसे दे पा रहे हैं?

हिन्दू विरोध में बदलता बांग्ला देश का आरक्षण आंदोलन

बांग्लादेश इस समय आरक्षण विरोधी आंदोलन के चलते गंभीर संकट से जूझ रहा है। आरक्षण के विरोध में संपूर्ण बांग्लादेश में हिंसा हो रही है। अब तक सरकारी आंकड़ों के मुताबिक डे? सौ से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। वैसे यह सरकारी आंकड़ा है असलियत में यह संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती है।चिंताजनक बात यह है कि अब यह आंदोलन हिंदू विरोध में बदलता जा रहा है।

नौकरियों की कमी से गुस्साए प्रदर्शनकारी उस प्रणाली को समाप्त करने की मांग कर रहे थे, जिसके तहत 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में हिस्सा लेने वालों के परिजनों को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत तक आरक्षण दिया जाता था। सरकार ने बड़े पैमाने पर छात्रों के विरोध प्रदर्शनों के बाद 2018 में इस पर रोक लगा दी थी, लेकिन जून में बांग्लादेश के हाई कोर्ट ने आरक्षण बहाल कर दिया था, जिसके बाद देश में फिर से विरोध प्रदर्शन शुरु हो गए।हालांकि हालात बिगड़ते देख कर सुप्रीम कोर्ट ने हाइकोर्ट के आरक्षण के आदेश पर रोक लगा दी है। बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि 93 प्रतिशत सरकारी नौकरियां योग्यता आधारित प्रणाली के आधार पर आवंटित की जाएं, पांच प्रतिशत 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में भाग लेने वालों के परिजनों और अन्य श्रेणियों के लिए दो प्रतिशत सीटें आरक्षित रखी जाएं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। इस बीच अब आरक्षण के खिलाफ जारी प्रदर्शन बांग्लादेश में हिंदुओं के विरोध में बदलता जा रहा है।बांग्लादेश में जारी हिंसक प्रदर्शनों के बीच एक हजार भारतीय छात्रों की वतन वापसी हो गई है। हालांकि अभी भी वहां हजारों की संख्या में छात्र फंसे हैं, जो जल्द घर आने की कोशिशों में जुटे हैं। बांग्लादेश में इस हफ्ते सरकारी नौकरियों के लिए विवादास्पद कोटा प्रणाली को लेकर बवाल मचा हुआ है।दरअसल बांग्लादेश में छात्रों के नेतृत्व में हो रहे विरोध प्रदर्शन शेख हसीना के नेतृत्व वाली सरकार की नौकरी कोटा प्रणाली के खिलाफ हैं, जो कुछ समूहों के लिए सरकारी नौकरियों का एक बड़ा हिस्सा आरक्षित करती है। प्रदर्शनकारियों का तर्क है कि यह प्रणाली भेदभावपूर्ण है और मेधावी उम्मीदवारों को सरकारी पद हासिल करने से रोकती है।आरक्षण के विरोध में बांग्लादेश में जो हिंसा हो रही है, वैसे तो यह उसका आंतरिक मामला है लेकिन इसके संदर्भ भारत से भी बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। बांग्लादेश में पहले 30 प्रतिशत आरक्षण बांग्लादेश मुक्ति संग्राम सेनानियों के परिवारों को मिलता था। लेकिन इस आरक्षण के खिलाफ बांग्लादेश में आंदोलन हुआ जिसके बाद इसे वापस ले लिया गया था। आंदोलन उचित भी था क्योंकि बांग्लादेश मुक्ति आंदोलन को आधी सदी हो गयी है, अब उनकी तीसरी पीढ़ी को आरक्षण देने का कोई मतलब नहीं। लेकिन नेता अपना स्वार्थ देखता है भले ही इसके लिए देश बर्बाद हो जाये। कुछ लोग अदालत में गये और यह फैसला ले आये कि 30 फीसदी आरक्षण फिर लागू किया जाये। संभवत: शेख हसीना की सरकार ने अदालत से इस तरह का फैसला करवाया और फिर उसे लागू कर दिया। इसका कारण यह है कि बांग्लादेश मुक्ति आंदोलन से ही शेख हसीना ही पार्टी बनी है और ज्यादातर स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार शेख हसीना की पार्टी में ही हैं। इस तरह 30 प्रतिशत आरक्षण का सीधा लाभ शेख हसीना की अवामी लीग पार्टी के कार्यकर्ताओं को मिलता है। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इसीलिए अति उत्साह में 30 प्रतिशत आरक्षण लागू किया। लेकिन उनको जनता के विरोध का अंदाजा नहीं था। आरक्षण लागू होते ही बांग्लादेश के लोग सड़कों पर आ गये और पूरे बांग्लादेश को हिंसा के हवाले कर दिया। परिणाम स्वरूप सैकड़ों लोग मारे गये। तमाम सरकारी भवनों को आगे के हवाले कर दिया गया। पूरा बांग्लादेश जल उठा। हिंसा कहीं भी हो उसको जायज नहीं ठहराया जा सकता है। कोटा विरोधी प्रदर्शनों को कॉर्डिनेट करने वाले नाहिद इस्लाम ने कहा, कि हम सामान्य रूप से कोटा प्रणाली के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम चाहते हैं, कि 1971 के स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए 30 प्रतिशत कोटा खत्म कर दिया जाए।

उन्होंने कहा, कि बांग्लादेश में कई युवाओं के लिए सरकारी नौकरियां ही एकमात्र उम्मीद हैं, और यह कोटा प्रणाली उन्हें अवसरों से वंचित कर रही है।प्रदर्शनकारियों का मानना है, कि ये रिजर्वेशन प्रधानमंत्री शेख हसीना की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए दिया जाता है और आरक्षण से उनकी सरकार को भारी फायदा मिलता है, क्योंकि आरक्षण लेने वाले उनके ही समर्थक हैं। आंदोलनकारियों का मानना है, कि कोटा का गलत फायदा उठाया जा रहा है। उनका तर्क है, कि कोटा भेदभावपूर्ण है और इसे योग्यता आधारित प्रणाली से बदला जाना चाहिए।भारत की तरह बांग्लादेश में भी सरकारी नौकरियों का क्रेज है, क्योंकि इसमें काफी अच्छा वेतन दिया जाता है। लेकिन, आधी से ज्यादा सरकारी नौकरियों में अलग अलग आरक्षण व्यवस्था है।प्रदर्शनकारियों का दावा है, कि वे किसी भी राजनीतिक समूह से जुड़े नहीं हैं। अल-जजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस आंदोलन को छात्र विरोधी भेदभाव आंदोलन के रूप में जाना जाता है। राजधानी में ढाका विश्वविद्यालय और चटगांव विश्वविद्यालय के हजारों छात्र आरक्षण विरोधी आंदोलन में शामिल हो गए हैं। और फिर यह देश के अन्य विश्वविद्यालयों में भी फैल गया है।लेकिन इस बीच कुछ ऐसी वीडियोज भी सामने आई है, जो इस बात की तस्दीक कर रहा है कि यह विरोध प्रदर्शन अब हिंदू विरोधी होते जा रहे हैं।सोशल मीडिया पर बांग्लादेश से वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे लेकर दावा किया जा रहा है ।

(मनोज कुमार अग्रवाल-विभूति फीचर्स)

श्री स्वामी जगन्नाथ जी का भक्तों को बांटा गया महाप्रसाद

कानपुर। श्री यज्ञसैनी वैश्य नवयुवक मण्डल हलवाई समाज के तत्वाधान मे भगवान श्री जगन्नाथ स्वामी के महाप्रसाद भोग भंडारे के कार्यक्रम का आयोजन वेद गेस्ट हाउस सिविल लाइन मे आयोजित किया गया कार्यक्रम की शुरुआत श्री जगन्नाथ स्वामी जी की आरती से हुआ।कार्यक्रम मे सुबह 10 बजे आरती हुई और उसके बाद बाल भोग आयोजित हुआ बाल भोग मे स्वादिस्ट तरह तरह प्रकार को पकौड़ी और हलवे का भोग आये श्रद्धांलुओं को दिया गया श्री जगन्नाथ स्वामी की आरती के पश्चात मशहूर गायक मुकुल बंधुओ द्वारा मधुर मधुर भजनो का रसपान कराया गया भजनो मे, बाके बिहारी कजरारे तेरे मोटे मोटे नैन नजर ना लग जाये और जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जय जैसे भजनो को सुना कर आये श्रद्धांलुओं को मन्त्रमुक्त कर दिया तो वही श्री कृष्ण-राधा की सुन्दर मनमोहक झांकी और फूलो की होली की प्रस्तुति की गई कार्यक्रम मे आये श्रद्धांलुओं ने भगवान के मधुर भजनो का आनंद लिया ।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि शपथकर्ती का नाम जन्म प्रमाण पत्र में रिंकी शिवहरे अंकित है तथा आधार में शपथकर्ती का नाम रिंकी अंकित है। रिंकी शिवहरे एवं रिंकी एक ही महिला का नाम है जो सत्य व सही है। प्रमाणीकरण दिनांक 26.7 को अहाता कचेहरी कानपुर नगर में किया गया।

विकास गुप्ता
पत्नी/ रिंकी
निवासी 96/2 बाबूपुरवा कालोनी,
किदवई नगर, कानपुर नगर

अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में सबला कमला

इस साल के अंत में दुनिया के सबसे ताकतवर लोकतंत्र संयुक्त राज्य अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में दावेदारी से लगता है कि उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की किस्मत चमक सकती है। अब तक राष्ट्रपति पद के लिये डेमोक्रेट प्रत्याशी के रूप में मजबूत दावेदारी कर रहे जो बाइडेन ने इस चुनावी दौड़ से अपने को अलग कर लिया है। बाइडेन ने यह कदम बढ़ती उम्र के चलते उन पर रेस से बाहर होने के लिये बढ़ रहे दबाव के बीच उठाया। रिपब्लिकन प्रत्याशी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से टीवी बहस में पिछड़ने के बाद लगता था कि उम्रदराज बाइडेन के मुकाबले ट्रंप सशक्त दावेदार हैं, लेकिन कमला हैरिस के डेमोक्रेटिक प्रत्याशी के रूप में सामने आने से तस्वीर बदल गई है। अब ट्रंप बाइडेन की जगह सबसे ज्यादा उम्रदराज प्रत्याशी बन गए हैं।बहरहाल, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की उम्मीदवारी का समर्थन किया है। जिससे अब यह चुनाव दिलचस्प हो चला है। अमेरिकी इतिहास में कमला हैरिस राष्ट्रपति पद के लिये पहली अश्वेत महिला दावेदार हैं। डेमोक्रेट्स के लिये यह एक ऐसा जोखिम जो उन्हें उठाना पड़ेगा। दरअसल, ट्रंप अमेरिका में श्वेतवाद के प्रबल समर्थक हैं। ऐसा ही जोखिम बाइडेन ने कमला को उपराष्ट्रपति पद के लिये चुनकर उठाया था। बहरहाल, अमेरिका में धीरे-धीरे डेमोक्रेट कमला के पक्ष में खुलकर सामने आने लगे हैं। बहरहाल, कमला की दावेदारी पर अगले महीने शिकागो में होने वाले डेमोक्रेट्स के राष्ट्रीय सम्मेलन में अंतिम मोहर लगेगी। कमला के लिए धनात्मक पक्ष यह है कि वे बाइडेन के बाद दूसरे नंबर के संवैधानिक पद पर विराजमान हैं। जाहिर है कि डेमोक्रेट्स एक महिला व एक अश्वेत प्रत्याशी की दावेदारी को शायद ही नकार सकें। हालांकि, उपराष्ट्रपति कार्यकाल की कुछ नाकामियों का खमियाजा भी कमला को भुगतना होगा। खासकर अवैध प्रवासियों वाले मुद्दे पर उनकी आलोचना हुई है। हालांकि, गर्भपात के अधिकारों के मुद्दे पर उनकी कामयाबी रही है। बहरहाल, अब कमला की दावेदारी से ट्रंप के लिये चुनौतियां बढ़ गई हैं। हालांकि, अभी कमला की दावेदारी को महत्वाकांक्षी डेमोक्रेट्स की चुनौती मिल सकती है। फिलहाल, कमला हैरिस के आने से अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव खासा दिलचस्प हो गया है। रिपब्लिकन को डेमोक्रेट्स के विरोध के लिये नये मुद्दे गढ़ने पड़ेंगे।

वहीं दूसरी ओर भारत में कमला हैरिस की राष्ट्रपति पद की दावेदारी सामने आने से खासा उत्साह है। दरअसल, भारतीय मूल की मां और जमैका मूल के पिता डॉनल्ड हैरिस की बड़ी संतान कमला को भारतवंशी की तरह देखा जाता है। हालांकि, कहना कठिन है कि उनका भारत व भारतीय संस्कारों से लगाव कितना भावनात्मक और कितना राजनीतिक है। अमेरिका में भारतीयों का एक वर्ग मानता है कि वे भारतीयों के बजाय अफ्रीकी समुदाय के अश्वेतों के मुद्दों पर अधिक सक्रिय रही हैं। हालांकि, वह अपनी भारतीय मूल की पहचान का जिक्र भारतीयों के बीच बखूबी करती रही हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव में भी वे भारतवंशियों को लुभाने के लिये अपने अतीत व तमिलनाडु में अपनी ननिहाल से जुड़े अनुभवों का जिक्र करती रही हैं। निस्संदेह, कमला एक बहुआयामी व्यक्तित्व की धनी राजनेता हैं। यही वजह है कि उपराष्ट्रपति पद के लिये कमला हैरिस के चयन के समय बाइडेन ने कहा था कि मैं देश के लिये नया नेतृत्व तैयार कर रहा हूं। लगता है आज उनके राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी बनने से वह घड़ी आ गई है।उल्लेखनीय है कि चेन्नई में जन्मी उनकी मां श्यामला गोपालन ऐसे वक्त पर सात समुंदर पार अमेरिका जाने का साहस जुटा सकी थी, जब अकेली लड़की को विदेश पढ़ाने की अनुमति देना बेहद मुश्किल माना जाता था। दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक करने के बाद वह वर्ष 1958 में न्यूट्रीशियन और एंडोक्रोनोलॉजी में पीएचडी करने अमेरिका गई थीं। बाद में ब्रेस्ट कैंसर के क्षेत्र में शोधार्थी बनीं। कालांतर में बर्कले में मानवाधिकारों के लिये संघर्ष करते हुए श्यामला डॉनल्ड हैरिस के संपर्क में आईं और उनसे विवाह किया। बाद में हैरिस से तलाक होने के बाद श्यामला ने भारतीय संस्कारों के साथ कमला व उनकी बहन माया की परवरिश की।आज भले ही कमला अमेरिका में प्रतिष्ठित अश्वेत नेता हों, लेकिन उन्होंने भारत से अपने जुड़ाव को कभी नकारा नहीं। कैलिफोर्निया के ऑकलैंड में जन्मी कमला ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की। फिर कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री लेकर वकालत शुरू की। वर्ष 2014 में यहूदी वकील डगलस एम्पहॉप से यहूदी व भारतीय परंपराओं से विवाह रचाया। वैसे उनकी छवि अफ्रीकी अमेरिकी राजनेता के रूप में बनी है। एक वजह यह भी है कि बाइडेन ने अमेरिका में भारतीय व अफ्रीकी मूल के निर्णायक वोटों के मद्देनजर कमला की राष्ट्रपति पद की दावेदारी का समर्थन किया है। आज अमेरिका में कमला हैरिस की छवि एक उदार, आधुनिक मूल्यों की पक्षधर तथा मानवाधिकारों के लिये संघर्ष करने वाली महिला के रूप में बनी है।

अपनी समस्या हमें बतायें

आपके साथ या आपके आस-पास कोई घटना, दुर्घटना, भ्रष्टाचार, जुर्म हुआ है या उत्पीड़न हुआ है अथवा आपके क्षेत्र की समस्या है और आपकी समस्या जायज है तो आपकी समस्याओं के समाधान हेतु सम्बन्धित उच्च अधिकारियों एवं शासन-प्रशासन तक पहुंचाने के लिये बी पी एस न्यूज आपके साथ है। आपकी खबर शत् प्रतिशत प्रकाशित की जायेगी। एवं आपका नाम व नम्बर आपके अनुसार प्रकाशित या पूर्णतया गुप्त रखा जायेगा।

दिये गये नम्बर पर काल करें या हमें ई मेल करें।

फोन नं.- 8423454502, bps.knp786@gmail.com

आवश्यक सूचना

प्रिय ग्राहकों/विज्ञापनदाताओं को सूचित किया जाता है कि बी.पी.एस. न्यूज समाचार पत्र में नगद भुगतान की व्यवस्था नहीं है। कृपया चेक/डी.डी. बी पी एस न्यूज के नाम से ही चेक आदि भेजें। नगद भुगतान की व्यवस्था नहीं है। नगद भुगतान करने पर विज्ञापनदाता स्वयं जिम्मेदार होंगे। - सम्पादक

आवश्यकता है

बी पी एस न्यूज राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक, साप्ताहिक समाचार पत्र व ऑनलाइन न्यूज चैनल (पोर्टल) के लिये समस्त तहसीलों एवं ब्लाक स्तर पर ब्यूरो चीफ, संवाददाताओं, छायाकार तथा विज्ञापन प्रतिनिधियों युवक-युवतियों की आवश्यकता है।

सम्पर्क करें -:
मो.: 8423454502
email:bps.knp786@gmail.com

विकलांग एसोसिएशन ने सामूहिक विवाह के लिए लगाया पंजीकरण शिविर

कानपुर। विकलांग एसोसिएशन ने शास्त्री नगर सेन्ट्रल पार्क, बगिया में सामूहिक विवाह के लिए पंजीकरण शिविर का आयोजन किया। शिविर में 13 आवेदन प्राप्त हुये।148 दिव्यांगजन के आवेदन विवाह हेतु लम्बित है/ दिव्यांग व गरीब व्यक्तियों का सामूहिक विवाह 09 नवम्बर को आयोजित किया जायेगा।एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेन्द्र कुमार ने बताया की दिव्यांग लड़की से स्वस्थ लड़के द्वारा विवाह करने पर सरकार से पुरस्कार के रूप में 20 हजार, शारीरिक रूप से स्वस्थ लड़की दिव्यांग लड़के से विवाह करेगी तो उन्हें 15 हजार व दोनों के दिव्यांग होने पर 35 हजार रूपये सरकारी सहायता दिलायी जायेगी।विकलांग एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेन्द्र कुमार ने बताया की गरीब व अनाथ दिव्यांग लड़कियों के विवाह के लिये एसोसिएशन ने घर बसाओ – पुण्य कमाओ कन्यादान योजना शुरू की है। ऐसे व्यक्तियों को कन्यादान योजना में शामिल किया जायेगा जिनके पुत्री नहीं है और वो कन्यादान करने के इच्छुक हों। इसके लिए उन्हें लिखित अनुरोध करना होगा।वीरेन्द्र कुमार ने कहा की दिव्यांग व्यक्तियों के विवाह में बहुत समस्या आ रही है। दिव्यांग लड़कियों के विवाह के लिये आवेदन नाम मात्र ही आते हैं। जबकि दिव्यांग लड़कों के आवेदन अधिक आते हैं। दिव्यांग व्यक्तियों का विवाह न हो पाने के कारण वो मानसिक तनाव में रहते हैं।वीरेन्द्र कुमार ने बताया की सुबह 9 बजे से 11 बजे तक प्रतिदिन शास्त्री नगर सेन्ट्रल पार्क बगिया में सामूहिक विवाह के लिये आवेदन प्राप्त किये जा सकते हैं। शिविर में राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेन्द्र कुमार के अलावा अल्पना कुमारी,अरविन्द सिंह,राहुल कुमार,गौरव कुमार,वैभव दीक्षित, रंजीत कुमार,जितेन्द्र गुप्ता,दिलिप कुमार,अनुराधा गुप्ता,सीमा कुशवाहा,याशमीन, त्रिप्ती खरे, रूखसार आदि शामिल थे।

राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी ने डी.सी.पी. साऊथ को सौंपा ज्ञापन, डी.सी.पी. ने मांगों पर जल्द कार्यवाही का दिया भरोसा

दिव्यांगजन अधिनियम 2016 सभी थानों में लागू करने, थानों में रैम्प बनाने व दिव्यांग उत्पीड़न कि रिपोर्ट दर्ज करने के मांग

बीपीएस न्यूज

कानपुर। राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी ने आज डी.सी.पी. साऊथ को ज्ञापन सौंप कर दिव्यांगजन अधिनियम 2016 सभी थानों में लागू करने, थानों में रैम्प बनाने व दिव्यांग उत्पीड़न कि रिपोर्ट थानों में दर्ज करने के मांग की है/डी.सी.पी. साऊथ रवीन्द्र कुमार ने मांगों पर जल्द कार्यवाही का भरोसा दिया।पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेन्द्र कुमार ने कहा कि अधिकारियों को दिव्यांगजन अधिनियम की जानकारी नही है जिसके कारण दिव्यांगजन अधिनियम के तहत दिव्यांगजन की रिपोर्ट थानों में नहीं दर्ज हो पा रही है। अधिकतर थानों में रैम्प न होने की वजह से दिव्यांगजन अपने उत्पीडन की रिपोर्ट थानों में दर्ज करने नहीं जा पाते है। वीरेन्द्र कुमार कुमार ने कहा कि थानों में दिव्यांगजन के साथ सम्मान जनक व्यवहार होना चाहिए। सम्मान जनक व्यवहार न होने से दिव्यांगजन अपने को उपेक्षित महसूस करते हैं।डी.सी.पी. साऊथ ने सभी मांगों पर कार्यवाही करने का भरोसा दिया है/आज ज्ञापन देने वालों में राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेन्द्र कुमार के जिला अध्यक्ष अलावा राहुल कुमार, प्रदेश अध्यक्ष आनन्द तिवारी,अल्पना कुमारी, गुड्डी दीक्षित, वैभव दीक्षित,तृप्ति खरे,अनुराधा गुप्ता, सीमा कुशवाहा, याशमीन, सरला, जितेन्द्र गुप्ता , ममता, उमाशंकर आदि शामिल थे।

चारा मशीन में साड़ी फंसने से घायल महिला की इलाज के दौरान मौत

बीपीएस न्यूज

कानपुर। घाटमपुर के चतुरीपुर गांव में चारा कतरने के दौरान महिला इंजन बंद करने के लिए जा रही थी, इस दौरान महिला की साड़ी इंजन के पट्टे में फंस गई। हादसे में महिला गंभीर घायल हो गई। परिजन आनन-फानन महिला को पतारा सीएचसी लेकर पहुंचे। जहां डाक्टर ने प्राथमिक उपचार कर गंभीर हालत में कानपुर के हैलट अस्पताल रेफर कर दिया गया।जहां इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। घाटमपुर थाना क्षेत्र के चतुरीपुर गांव निवासी मोकल सिंह यादव ने बताया कि उनकी 33 वर्षीय पत्नी संगीता सिंह घर के बाहर डीजल इंजन की चारा कटाई मशीन से चारा काट रही थी। इस दौरान वह चारा काटने के बाद इंजन बंद कर वापस लौटते समय उसकी साड़ी अचानक इंजन के पट्टे में फंस गई। जिससे पट्टे में फंसकर कई फेरे घूमने से महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजन आनन-फानन महिला को पतारा सीएचसी लेकर पहुंचे।जहां डाक्टर ने महिला को प्राथमिक उपचार कर गंभीर हालत में हैलट अस्पताल रेफर कर दिया गया। जहां इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना की जांच परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना की जांच पड़ताल करने के साथ महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।?घाटमपुर थाने के क्राइम इंस्पेक्टर खुर्शीद अहमद ने बताया कि महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।परिजन आनन-फानन महिला को पतारा सीएचसी लेकर पहुंचे। जहां डाक्टर ने महिला को प्राथमिक उपचार कर गंभीर हालत में हैलट अस्पताल रेफर कर दिया गया। जहां इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना की जांच परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना की जांच पड़ताल करने के साथ महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।?

महासम्मेलन में जीएसटी से संबंधित नए प्रावधानों की जानकारी की साझा

कानपुर । लघु उद्योग भारती कानपुर संभाग की वार्षिक सभा एवं उद्यमी महासम्मेलन संपन्न हुआ । इस कार्यक्रम में लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष घनश्याम दास ओझा प्रदेश अध्यक्ष मधुसूदन दादू प्रदेश महामंत्री भरत अलीगढ़ से गौरव मित्तल मुख्य रूप से उपस्थित हुए। कार्यक्रम में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आशीष बंसल ने नए बजट में आए हुए इनकम टैक्स एवं जीएसटी से संबंधित नए प्रावधानों की जानकारी उपस्थित उद्यमियों से साझा की।

इसी प्रकार कार्यक्रम में भारत की बढ़ती हुई जीडीपी के अनुसार एचडीएफसी म्युचुअल फंड एवं आइसीआइसीआइ म्युचुअल फंड से आए हुए अधिकारियों ने उद्यमियों को नए निवेश के लिए आकर्षक फंडो की जानकारी प्रदान की।

कार्यक्रम में लघु उद्योग भारती कानपुर संभाग, झांसी, एवं कन्नौज के लगभग 225 उद्यमियों ने भाग लियाद्यकानपुर संभाग के अध्यक्ष अमन घई ने राष्ट्रीय अध्यक्ष घनश्याम दास ओझा के समक्ष लघु उद्योगों को आ रही समस्याओं से अवगत कराया राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इन सभी समस्याओं के निवारण का आश्वासन दिया एवं पूरा भरोसा दिया कि लघु उद्योग भारती की केंद्रीय इकाई इसे पूरी प्रमुखता से सरकार के समक्ष रखकर जल्द से जल्द इसका निवारण करेगी।कार्यक्रम का संचालन लाडली प्रसाद ने किया एवं धन्यवाद प्रस्ताव संदीप अरोरा ने दिया कानपुर संभाग से महामंत्री संदीप अवस्थी, उपाध्यक्ष अजय गुप्ता, विपिन खुल्लर,अनुराग मालवीय, सलिल गुप्ता, पुनीत गुप्ता, श्रवण अग्रवाल,अनुज गुप्ता इत्यादि लोग उपस्थित रहे।

हेपेटाइटिस से घबराने की आवश्यकता नहीं

बीपीएस न्यूज

कानपुर। राष्ट्रीय वायरल हेपिटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में एक सेमिनार का आयोजन किया गया।

इस आयोजन का उद्देश्य वायरल हेपेटाइटिस के जांच के एवं इलाज के आधुनिक तरीकों के बारे में चर्चा करना था।

कार्यक्रम का उद्घाटन मेडिकल कॉलेज की उप प्रधानाचार्या डॉ ऋचा गिरी एवं प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर आरके सिंह द्वारा लैंप प्रज्वलित करके किया गया। इस कार्यक्रम के आरंभ में डॉ विनय कुमार, विभागाध्यक्ष गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग द्वारा राष्ट्रीय वायरल हेपिटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम के बारे में संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया गया। उसके उपरांत डॉक्टर समरजीत कौर सह आचार्य कम्युनिटी मेडिसिन, डॉ विकास मिश्रा आचार्य माइक्रोबायोलॉजी विभाग एवं डॉक्टर ध्रुव ठाकुर सहायक आचार्य गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग द्वारा व्याख्यान प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार के हेपिटाइटिस वायरस की संरचना, इन वायरस से होने वाली बीमारियों से संबंधित आंकड़ों के बारे में एवं हेपेटाइटिस बी के इलाज की गाइडलाइन के बारे में विचार विमर्श हुआ। डॉ विनय कुमार द्वारा संक्रमित मां से बच्चों में हेपेटाइटिस बी रोकने के तरीकों को बताया गया। इस अवसर पर डॉ मनीष सिंह नोडल पीएमएसएसवाई, डॉ सौरभ अग्रवाल उपस्थित रहे।

अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम लागू करा निभाएंगे अधिवक्ता धर्म : सुरेंद्र मैथानी

राजस्थान कर्नाटक की तर्ज प्रदेश में भी लागू हो अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम

बीपीएस न्यूज

कानपुर ।अधिवक्ताओं का प्रतिनिधिमंडल विधायक सुरेंद्र मैथानी से उनके आवास पर मिला और पूर्व में अधिवक्ता सामूहिक बीमा योजना लागू कराने में उनके योगदान के लिए उनका अंगवस्त्र पटका और माला पहनाकर आभार व्यक्त किया।इस अवसर पर पंडित रवीन्द्र शर्मा पूर्व अध्यक्ष लॉयर्स एसोसिएशन ने बताया कि अधिवक्ता अधिवक्ता परिवारों पर निरंतर हमले हो रहे हैं अधिवक्ताओं के खिलाफ झूठी रिपोर्ट लिख उनकी गिरफ्तारी की जा रही है जिसको लेकर प्रशासन और अधिवक्ताओं के मध्य कई बार टकराव की स्थिति आ चुकी है संरक्षण अधिनियम में अन्य के साथ अधिवक्ताओं के विरुद्ध रिपोर्ट लिखे जाने और अधिवक्ताओं की गिरफ्तारी से पूर्व बार संघों को लिखित सूचना दिए जाने का प्रावधान लागू होने से अधिवक्ताओं और प्रशासन के मध्य टकराव की स्थिति से बचाव होगा।

संरक्षण अधिनियम को लागू किए जाने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई ।ड्राफ्टिंग कमेटी दिसंबर 2023 में सभी जनपदों से सुझाव भी ले चुकी है किंतु अभी संरक्षण अधिनियम लागू नहीं हुआ।29 जुलाई से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम के लिए आवाज उठा अपने अधिवक्ता होने का फर्ज निभाएं। मुख्यमंत्री से मिल अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम लागू कराए।विधायक सुरेंद्र मैथानी ने मुख्यमंत्री को संबोधित पत्र प्राप्त कर कहा योगी सरकार अधिवक्ता हितैषी है और अधिवक्ता कल्याण की कई योजनाएं लागू कर चुकी है

अधिवक्ता होने के नाते संरक्षण अधिनियम लागू कराना मेरा धर्म है और मैं मुख्यमंत्री से मिल और सदन में प्रकरण रखते हुवे, अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम लागू करा अपना अधिवक्ता धर्म निभाऊंगा।प्रमुख रूप से आशीष गुप्ता संजीव कपूर राकेश सिद्धार्थ सत्यम शुक्ला शिवम गंगवार विकास गुप्ता रुखसार जीतू कश्यप अतुल सिंह के के यादव आदि रहे।

जन जागरुकता रैली निकाल विभिन्न जगहों पर किया वृक्षारोपण

बीपीएस न्यूज

कानपुर। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत संपूर्ण कानपुर नगर परिक्षेत्र में वृक्षारोपण हेतु जन जागरूकता रैली निकाल कर भिन्न-भिन्न चयनित स्थानों में वृक्षारोपण कार्यक्रम किया जा रहा है जिसका विवरण इस प्रकार है फूलबाग गणेश उद्यान में मुख्य अतिथि पुलिस उपायुक्त/पुलिस आयुक्त यातायात/यातायात निरीक्षक पूर्वी जोन के कर कमलों द्वारा वृक्षारोपण किया गया अरावली पार्क शताब्दी नगर पनकी में मुख्य अतिथि थाना प्रभारी द्वारा वृक्षारोपण किया गया 4. रामलीला मैदान जी-ब्लॉक गुजैनी में मुख्य अतिथि सहायक पुलिस आयुक्त गोविंद नगर/ यातायात निरीक्षक दक्षिण जोन के द्वारा किया गया रोशन-नगर रावतपुर में मुख्य अतिथि यातायात निरीक्षक सेंट्रल जोन के द्वारा वृक्षारोपण किया गया उपरोक्त कार्यक्रम में मुख्य रूप से हमारी संस्था के प्रदेश अध्यक्ष विक्की जायसवाल (राजीव), प्रदेश महामंत्री मोनू यादव, सचिव रुहिद खान, कोषाध्यक्ष दिनेश भदौरिया, उपाध्यक्ष राजू जायसवाल, जितेंद्र रतन, सुरेश मिश्रा, मंत्री राजेश गुप्ता, जितेंद्र कुमार शुक्ला, वसीमुद्दीन, पंकज तिवारी शिवम दुबे, अनिल पाल, संदीप गुप्ता, संदीप पाण्डेय, विपिन जायसवाल, सोनू यादव, राजवीर सिंह यादव, राशिद सिद्दीकी, राजू सक्सेना, सजीवन, वसीम अहमद सिद्दीकी आदि लोग मौजूद रहे ।

नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हुआ

बीपीएस न्यूज

कानपुर।निश्शुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन बिठूर स्थित रॉयल ड्रीम वर्ल्ड इंटर कॉलेज में पारस यश कोठारी हॉस्पिटल के सहयोग से निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें 100 से ज्यादा अभिभावकों, शिक्षकों और बच्चों ने अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराया।स्वास्थ्य शिविर में ब्लडप्रेशर,ब्लडशुगर आदि जांचे मुफ्त में की गई,साथ ही साथ डॉ राखी (फिजीशियन) ने अभिभावकों एवं बच्चों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को सुना और उन्हें सलाह भी दी कि इस मौसम में कैसे संचारी रोगों से बचाव किया जाए। प्रधानाचार्या सपना सिंह ने इस शिविर के सफल आयोजन के लिए डॉ राखी,गौरव चौरसिया तथा उनकी टीम को धन्यवाद एवं बधाई दी।वही इस शिविर में निखिल बाजपेई,अमित कुशवाहा आदि लोग उपस्थित रहे।

साल भर के भीतर ही 'दगा' देने लगे टैबलेट

बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों के डिजिटलीकरण के लिए प्रदेश भर में दिए गए थे टैबलेट

- कनेक्टिविटी काफी कम होना
- बैटरी बैकअप कम होने से बिजली नहीं आने पर जल्द बन्द हो जाता है टैबलेट
- 4जी सिम से ही संचालित होने से ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में संचालन काफी मुश्किल

कानपुर। परिषदीय विद्यालयों को डिजिटल करने के लिए दिए गए टैबलेट को साल भर पूरे नहीं हुए परन्तु अब वे दिक्कतें देने लग गए हैं। आलम यह है कि टैबलेट के संचालन में शिक्षकों को पसीने छूट रहे हैं। दूरदराज ही नहीं ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में टैबलेट पर काम करना काफी कठिन हो रहा है। परिषदीय विद्यालयों में दैनिक कामकाज के लिए रखे गए 12 रजिस्टरों को पूरी तरह से डिजिटल करने के लिए सरकार ने सभी विद्यालयों को ये टैबलेट दिए हैं। विद्यालयों में इन पर काम शुरू भी हो गया है लेकिन बीते अप्रैल में मिले टैबलेट को चलाने की समस्याएं आने लगी हैं। टैबलेट के लिए सरकार ने 2023 में ही टेंडर किया था और पिछले वर्ष ही इसकी आपूर्ति हुई है, लिहाजा उस हिसाब से शिक्षकों द्वारा इसे पुराना वर्जन कहा जा रहा है।जानकारों के अनुसार स्कूल शिक्षा महानिदेशालय को रोज दो से ढ़ाई सौ शिकायतें टैबलेट के संचालन को लेकर मिल रही हैं। कुछ शिकायतें तो वीडियो काल से दुरुस्त किये जा रहे हैं लेकिन जहां गम्भीर समस्याएं रहती हैं, वहां महानिदेशालय से तकनीकी टीम जाकर गड़बड़ियों को दुरुस्त कर रही है या फिर टैबलेट बदले जा रहे हैं।

लगातार रोहांगियाओ की बढ़ती संख्या पर विधायक ने जताई चिंता

बीपीएस न्यूज

कानपुर। कानपुर में लगातार रोहांगियाओ की बढ़ती संख्या पर विधायक ने जताई चिंता अधिकारियों से कहा अभिलंब करें कार्रवाई अन्यथा मुख्यमंत्री की चौखट पर भी यह विषय जाएगा ।गोविंद नगर विधानसभा के विधायक सुरेंद्र मैथानी ने बताया के चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय(ष्टरू) के बोर्ड का मेंबर होने के नाते बोर्ड की बैठक में इस विषय पर जानकारी प्राप्त करने के लिए, जब रोहांगियों के,ष्टरू की जमीन पर बसे होने की जानकारी के संबंध में पूछा, तो पता चला कि हमारे सीएसऐ की जमीन पर, जीटी रोड से लगे हुए काफी बड़े भूभाग पर,रोहांगिया आकर बस गए हैं, जिन्होंने प्लास्टिक की मोमिया लगाकर अपने घर बना लिए हैं,वहीं कुछ ने छप्पर आदि डालकर अपना निवास बनाकर, अवैध रूप से निवास कर रहे हैं। यह भी जानकारी आई कि वहां पर सूखे नशे का कारोबार हो रहा है तथा आसपास के क्षेत्र में क्राइम भी बढ़ रहा है ।विधायक जी ने सारे घटनाक्रम से कानपुर के जिलाधिकारी को जिले की विकास बैठक में सार्वजनिक रूप से अवगत कराया ।जिस पर ष्टरूकानपुर ने अभिलंब कार्रवाई का आश्वासन दिया ।तत्पश्चात कानपुर नगर पुलिस कमिश्नर की कैंप कार्यालय में जिले की कानून व्यवस्था की बैठक में उक्त विषय कमिश्नर के संज्ञान में दिया। तत्काल उक्त बैठक में मौके पर ही,पुलिस कमिश्नर कानपुर ने डीसीपी को निर्देशित किया कि अभिलंब इस पर कार्रवाई करें ।विधायक ने कहा की कानून सम्मत जो भी कार्रवाई होनी चाहिए वह कार्रवाई अभिलंब की जाए। क्योंकि कानपुर नगर की जनता के हितों की रक्षा करना मैं जनप्रतिनिधि होने के नाते से अपना कर्तव्य मानता हूं और जिसे हर हाल में पूरा करूंगा ।विधायक ने कहा कि मुझे भरोसा है कि जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन मिलकर कानपुर के अंतर्गत अन्य भूभाग(जमीनों) पर भी इस प्रकार की गतिविधियों के संचालन पर अभिलंब रोक लगाकर तत्काल कानून सम्मत कार्रवाई करेंगे ।विधायक ने कहा कि सोमवार से प्रारंभ होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदन में भी मैं मुख्यमंत्री के संज्ञान में उक्त गंभीर विषय को दूंगा।

कानपुर हवाई अड्डे का नाम चंद्रशेखर आजाद के नाम पर हो : भारतीय आजाद मंच

बीपीएस न्यूज

कानपुर। कानपुर जिला में स्थित हवाई अड्डे का नाम शहीद चंद्रशेखर आजाद हवाई अड्डा किए जाने की मांग को लेकर मंगलवार को भारतीय आजाद मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर मिश्रा अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने कानपुर जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन दिया। भारत के अलग-अलग राज्यों में कुछ ऐसे रेलवे स्टेशन,हवाई अड्डे भी हैं जिनका नाम क्रांतिकारियों या स्वतंत्रता सैनानियों के नाम पर रखा गया है। कानपुर चकेरी हवाई अड्डे का नाम आजादी के नायक चंद्रशेखर आजाद के नाम पर किए जाने का अनुरोध किया गया है जिससे बाहर से आने वाले यात्रियों, अभ्यर्थियों व अन्य लोगों को भारत के संघर्ष से मिली आजादी के इतिहास को जानने का अवसर मिलेगा ।राष्ट्रीय प्रवक्ता दीपक पाण्डेय ने ज्ञापन में कहा गया है कि देश की आजादी में कानपुर नगर स्वत्रंता संग्राम का एक महत्वपूर्ण केन्द्र रहा है अब हमारा शहर कानपुर कई महान क्रांतिकारियों का साक्षी बना है, कहा जाता है कि शहीद ए आजम भगत सिंह अन्य क्रातिंकारियों के साथ पहली मुलाकात शहीद चन्द्रशेखर आजाद से कानपुर में हुई थी ।भारतीय स्वत्रंता संग्राम में चन्द्रशेखर आजाद का नाम स्वर्णीम अक्षर से लिखा है। इसलिए हवाई अड्डे का नाम उनके नाम होना चाहिए। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर मिश्रा, प्रवक्ता दीपक पाण्डेय, सचिव राहल द्विवेदी,सुभाष मिश्रा प्रदीप जयसवाल,मंत्री आदित्य साहू, अमरदीप,प्रदीप जायसवाल मंडला अध्यक्ष, सूरज, नवीन पंडित उपस्थित थे।

राष्ट्रीय बजट अधिवक्ताओं को निरंतर कर रहा निराश:रवीन्द्र शर्मा

बीपीएस न्यूज

कानपुर। प्रस्तुत केंद्रीय बजट पर कचहरी परिसर में परिचर्चा हुई जिसमें बोलते हुए पंडित रवीन्द्र शर्मा पूर्व अध्यक्ष लॉयर्स एसोसिएशन ने कहा कि आजादी के इतने वर्षों बाद ही अभी तक राष्ट्रीय स्तर पर अधिवक्ताओं की एक भी सामाजिक सुरक्षा योजना लागू नहीं की गई है।

अधिवक्ता समाज अपनी सामाजिक सुरक्षा हेतु बजट में निश्चित धनराशि का बजटीय प्रावधान किए जाने हेतु निरंतर प्रयासरत हैं हमने प्रधानमंत्री के कार्यालय नई दिल्ली जाकर और सांसदों के माध्यम से कानून मंत्री सहित प्रधान मंत्री को प्रतिवेदन दे अधिवक्ता पेंशन योजना अधिवक्ता स्वास्थ्य बीमा कवर योजना और युवा अधिवक्ता प्रोत्साहन योजना हेतु बजटीय प्रावधान किए जाने की मांग की। किंतु पूर्व की भांति इस वर्ष भी प्रस्तुत बजट में अधिवक्ताओं की पूर्ण उपेक्षा की गई, जबकि हमें विश्वास था इस बजट में अधिवक्ताओ की सामाजिक सुरक्षा के लिए ना कुछ जरूर किया जाएगा किंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ हमें ऐसा लगता है कि सरकार अधिवक्ताओं की सामाजिक सुरक्षा के प्रति कतई गंभीर नहीं है। एक बार फिर वकील खाली हाथ है किंतु हम अपनी सामाजिक सुरक्षा हेतु निरंतर प्रयासों में लगे रहेंगे ।परिचर्चा में प्रेम गुप्ता पूर्व अध्यक्ष सेल्स टैक्स बार एसोसिएशन अरविन्द दीक्षित पूर्व उपाध्यक्ष बार एसोसिएशन मो कादिर खां संजीव कपूर अखिलेश सिंह विष्णु पासवान शरद मिश्रा जे पी उत्तम हरिशंकर चतुर्वेदी शिवम गंगवार उमर दानिश कुरेशी आदि रहे।

आरटीओ कार्यालय में डीसीपी एसीपी मजिस्ट्रेट का पड़ा छापा

कानपुर। काकादेव थाना अंतर्गत आरटीओ में दलालों को एवं ऑफिस में डीसीपी एसीपी मजिस्ट्रेट का पड़ा छापा। आरटीओ में उच्च अधिकारियों को देखते ही दलालों में मची भगदड़ ।कानपुर के आरटीओ कार्यालय में बिना दलालो के कोई काम नही होता है। लाइसेंस बनाने से लेकर रिन्युअल तक का काम दलालो के ही माध्यम से किया जाता है। जितनी यह बात दलालो की सही है उतना यह भी सत्य है कि कार्यालय में आम आदमी का काम भी नही होता वही यदि दलाल साथ मे तो आर्टियो के बाबू सहजता से कार्य कर देते है। अब जब छापेमारी कर दलालो पर नकेल कसने के काम किया ही गया है तो, होना ये भी चाहिये कि उन बाबुओ पर भी नकेल कसी जाए जो बिना दलालो के जनता का काम नही करते।

पुरानी पेंशन बहाली को लेकर जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर धरना प्रदर्शन

हमारी मांग नहीं मानती तो शिक्षक समुदाय जेल भरो आंदोलन करेगा

बीपीएस न्यूज

कानपुर। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ शर्मा गुट) के प्रदेशीय नेतृत्व के आवाहन पर कानपुर नगर के माध्यमिक शिक्षकों द्वारा भारी संख्या में उपस्थित रहते हुए अपनी मांगों पुरानी पेंशन बहाली नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा,चयन बोर्ड अधिनियम की धारा 21,18 व 12 की पुन:

स्थापना तथा स्थानीय समस्याओं जैसे एन. पी.एस. खाते में धनराशि के हस्तांतरण में अनियमितता,चयन,प्रोत्रत वेतनमान एवं प्रमोशन जैसे प्रकरणों के निस्तारण में कार्यालय स्तर पर शिथिलता आदि के संबंध में जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय चुन्नीगंज कानपुर नगर में धरना एवं प्रदर्शन कार्यक्रम किया गया।

प्रदेशीय उपाध्यक्ष हेमराज सिंह गौर ने घरने में आये शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि उ. प्र. मा. शिक्षक संघ पुरानी पेंशन बहाली एवं नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा जैसी अत्यंत महत्वपूर्ण मांगों को लेकर विगत कई वर्षों से आंदोलित है परंतु उत्तर प्रदेश सरकार इन मुद्दों को लेकर लगातार उदासीनतापूर्ण रवैया अपनाए हुए है देश में पश्चिम बंगाल, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ झारखंड, हिमाचल प्रदेश आदि राज्यों ने पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल की है परंतु उत्तर प्रदेश सरकार इसओर कोई ध्यान नहीं दे रही है जिसके चलते शिक्षक समुदाय अपने भविष्य को लेकर अत्यंत दु:खी है, व उनके मन में रोष व्याप्त है तथा वह अपनी मांगों को लेकर सड़क से सदन तक संघर्ष करने को तैयार है और यदि सरकार तब भी हमारी मांग नहीं मानती तो शिक्षक समुदाय जेल भरो आंदोलन करेगा ।जिला मंत्री अनिल सचान में वित्त विहीन शिक्षक साथियों को समान कार्य हेतु सगान वेतन का मुद्दा उठाते हुए, उनकी दयनीय आर्थिक स्थिति से सभी को अवगत कराया!

ंडलीय मंत्री मोहित मनोहर तिवारी ने एनपीएस खातों में धनराशि के आवंटन को लेकर कार्यालय स्तर पर हो रहीं अनियमितता से जिला विद्यालय निरीक्षक को अवगत कराते हुए कहा कि पटल सहायक को इस संबंध में सचेत रहना चाहिए ।धरने का नेतृत्व कर रहे जिला अध्यक्ष राकेश तिवारी ने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को संबोधित मांग पत्र संबंधी ज्ञापन जिला विद्यालय निरीक्षक कानपुर नगर को प्रेषित किया ।धरना कार्यक्रम में राकेश तिवारी जिला अध्यक्षअनिल सचान जिला मंत्री,सम्बृद्धि मिश्रा, एन पी सिंह गौर, रमाशंकर तिवारी, रंजीत सिंह, जीतेन्द्र प्रताप द्विवेदी, सत्येंद्र सचान,मनीष मिश्रा, रामकुमार, जितेंद्र प्रताप, सुधीर सचान,अनुराग सचान आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।

शहर कांग्रेस कमेटी ने अघोषित बिजली कटौती व बिलों में हो रही अनियमितताओं के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया

कानपुर, शहर कांग्रेस कमेटी, कानपुर नगर द्वारा अघोषित बिजली कटौती व बिजली बिलों में हो रही अनियमितताओं के खिलाफ केस्को मुख्यालय के पास सिविल लाइंस में धरना दिया गया। जिसमें केस्को की बदहाल व्यवस्था और सरकार की गलत व्यवस्था और सरकार की गलत नीतियों के विरुद्ध बिगुल फूंका गया। धरने में शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नौशाद आलम मंसूरी पूर्व लोकसभा प्रत्याशी आलोक मिश्रा उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष पूर्व विधायक संजीव दारियावादी ,सोहेल अख्तर अंसारी, मदन मोहन शुक्ला ,पवन गुप्ता, नरेश चंद्र त्रिपाठी आदि ने संबोधित करते हुए प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि इतनी भीषण गर्मी और उमस का मौसम है जहां खाना खाने की जितनी जरूरत है, जीवन जीने के लिए उतनी ही बिजली की जरूरत है। लेकिन अघोषित बिजली कटौती ने आम जनमानस का जीवन दुर्लभ कर दिया है जनता नरक की जिंदगी जी रही है। बिजली कटौती की वजह से गर्मी और उमस के कारण वरिष्ठ नागरिक व बच्चे बीमार पड़ रहे हैं छात्रों की पढ़ाई नहीं हो रही है लोगों की नींद पूरी नहीं हो पाने से लोग बीमार पड़ रहे हैं वहीं दूसरी तरफ केस्को के त्रुटि पूर्ण बिलों के माध्यम से गलत वसूली की जा रही है उपभोक्ता को प्रीपेड मीटर के भुगतान पर उसको बिजली खर्च का विवरण नहीं मिल पा रहा है ।स्मार्ट मीटर की रफ्तार बहुत तेज है और मीटर खराब साबित हो रहे हैं जिसकी जांच की संपूर्ण व्यवस्था नहीं है शिकायत करने पर हिला हवाली की जाती है फॉल्ट सही होने में 15-15 घंटे लग जाते हैं नई कनेक्शन लेने पर दलाल व्यवस्था हावी है ऐसे में सिर्फ आम आदमी का उत्पीड़न हो रहा है जो कांग्रेस पार्टी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। धरने में सभी उत्साही कांग्रेस जन हाथ में पट्टियां लेकर उपभोक्ताओं का उत्पीड़न

बंद करोबिजली कटौती बंद करो न्याय दो, न्याय दो आदि नारे लगाते रहे धरने के समापन पर केस्को एम डी के नाम संबोधित 8 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन एम डी कीअनुपस्थिति में वागीश कुमार अधिशासी अभियंता (वाणिज्य) को दिया गया ।कार्यक्रम का संयोजन हरीश गुप्ता व पिंटू कुरील ने किया। धरने में प्रमुख रूप से शंकर दत्त मिश्रा,प्रतिभा अटल पाल, मनीष बाजपेई ,दिलीप शुक्ला, सुनीत त्रिपाठी, संजीव मिश्रा ,अमीन खान पूर्व पार्षद राकेश साहू, राम शंकर राय ,सुनील राठौर, हरीश बाजपेई, रामस्वरूप तिवारी, शबनम आदिल, कमल जायसवाल ,गुफरान अहमद चांद, साजिद सर,राजलक्ष्मी ,सुषमा पंत, रूपा,रजनी, ममता परिहार, राजू चंदेल, आजाद बौद्ध, फरदीन, मंकू ठाकुर ,अब्दुल तारिक ,अफरोज आलम ,संजय अवस्थी ,शकील मंसूरी, तनवीर खान मंटू, संजय बाथम ,शांतनु दीक्षित ,आतिफ रहमान ,आरके त्रिपाठी ,सुशील तिवारी ,निर्भय अवस्थी,विनय सोनकर,आशुतोष शुक्ला ,रामजी दुबे, चंद्रमणि मिश्रा, मनु पांडे आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।

बजट में यूपी को मिले 2.44 लाख करोड़ से प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग और ऊर्जा के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति होगी

केंद्रीय बजट उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की नीव रखने वाला: बीएल वर्मा

कानपुर। भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री केंद्रीय मंत्री बी एल वर्मा ने कहा कि केंद्रीय बजट गरीब, किसान, महिला और युवाओं को समर्पित है। इस बजट के माध्यम से उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की एक मजबूत नीव रखने का काम किया गया है। यह बजट रामराज्य के संकल्प को साकार करने वाला है। विपक्ष द्वारा बजट में उत्तर प्रदेश को कुछ नहीं मिलने की बात पूरी तरह निराधार है। बजट में उत्तर प्रदेश को सबसे अधिक अंश मिला है। यूपी में इंफ्रास्ट्रक्चर और उद्योग को उभारने के लिए 2.44 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है जो राज्य की प्रगति में मील का पत्थर साबित होगा।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बजट में कर्ज गारंटी योजना से यूपी की 20 लाख इकाइयों को जीवन दान मिलेगा व 22 लाख नए उद्यमी तैयार होंगे। प्रदेश के लगभग 100 आईटीआई कॉलेज अपग्रेड किए जाएंगे। इससे 3.5 लाख युवाओं को फायदा मिलेगा और इंटर्नशिप योजना में 2 लाख युवाओं को लाभ मिलेगा। प्रदेश में हाईवे निर्माण के लिए 40 हजार करोड रुपए मिलेंगे। प्रदेश में 10 नए राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए जायेंगे। प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में 2 हजार नई सड़कों का निर्माण होगा। प्रदेश में रेलवे डेवलपमेंट के लिए 19,848 करोड रुपए दिए गए हैं। झांसी से दतिया तक 23 किलोमीटर की लाइन पर तीन ट्रैक बनाए जाएंगे। पूर्वांचल के औडिहार से सादात तक 19.2 किलोमीटर रेल लाइन का दोहरीकरण होगा। प्रदेश में तीन नए औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे ।मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री बी एल वर्मा, क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल ने दीप प्रज्वलन कर बजट संगोष्ठी का शुभारंभ किया। दक्षिण जिलाध्यक्ष शिवराम सिंह एवं उत्तर जिलाध्यक्ष दीपू पांडे ने प्रतीक चिन्ह देकर मुख्य अतिथि का स्वागत किया। संगोठी में मुख्य अतिथि ने केंद्र मंत्री बी एल वर्मा ने शहर के प्रमुख उद्योगपति, व्यवसायी, वकील, विशिष्टजनो, चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रबुद्धजनो सहित विधायक, एमएलसी महापौर, जिला पंचायत अध्यक्ष, सहित सभी जनप्रतिनिधि एवं पार्टी कार्यकर्ताओ को बजट के बारे में विस्तार से जानकारी दी ।कार्यक्रम में एक बड़ी एलईडी पर पीपीटी के माध्यम से बजट की खूबियों को दिखाया गया। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने पिछड़ा वर्ग आयोग बनाकर पिछड़े वर्गो का सम्मान बढ़ाया है। विपक्षी पार्टियों ने सविधान बदलने का भ्रम फैलाकर मतदाताओं को भ्रमित करने का काम किया है। भाजपा 2017 की तरह ही 2027 में चुनाव जीत कर सरकार बनाएगी। प्रमुख रूप से महापौर प्रमिला पांडेय, सलिल विश्नोई, विधायक महेश त्रिवेदी, सुरेंद्र मैथानी, राहुल बच्चा सोनकर, सरोज कुरील, देवेश कोरी, कमलावती सिंह,जिलाध्यक्ष शिवराम सिंह,दीपू पांडेय, दिनेश कुशवाहा, स्वप्निल वरुण,पूर्व मंत्री बाल चंद्र मिश्र,सुरेश अवस्थी, रघुनंदन भदौरिया, सुनील नारंग, रामबहादुर यादव, विनोद मिश्रा,जसविंदर सिंह, मीडिया प्रभारी मनीष त्रिपाठी, प्रकाश वीर आर्य,नवीन पंडित, पूर्व पार्षद राजू बाजपेयी आदि मौजूद रहे।

योगी सरकार का आदेशः अपनी तहसील में ही निवास करें उपजिलाधिकारी और तहसीलदार

लखनऊ। जनता की समस्याओं को सुनने और समय पर उनकी समस्याओं का निस्तारण सुनिश्चित कराने के लिए योगी सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। गुड गवर्नेंस की अपनी प्रतिबद्धता का अनुकरण करते हुए सरकार ने प्रदेश भर की विभिन्न तहसीलों में तैनात उपजिलाधिकारी (एसडीएम) एवं तहसीलदार को अब उसी तहसील में निवास करने का आदेश जारी किया है। इस आदेश का उद्देश्य यह है कि उपजिलाधिकारी एवं तहसीलदार ज्यादा से ज्यादा समय अपनी तहसील में बिताएं एवं जनसामान्य की समस्याओं को सुनकर निर्धारित समयसीमा के अंतर्गत उसका निराकरण करने का प्रयास करें। इससे न सिर्फ अधिकारियों की, बल्कि सरकार की छवि में भी सुधार होगा। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की ओर से सभी मंडलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें मंडलायुक्त और जिलाधिकारियों को इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं।मुख्य सचिव की ओर से मंडलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को जो निर्देश दिए गए हैं, उसके अनुसार जनसमस्याओं का ससमय निराकरण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार की गुड गवर्नेंस की प्रतिबद्धता के लिए यह आवश्यक है कि तहसील स्तरीय प्रशासन पूरी सजगता व तत्परता से कार्य करें। इस निर्देशन व पर्यवेक्षण को सशक्त बनाने के लिए यह आवश्यक है कि संबंधित तहसीलदार एवं उपजिलाधिकारी जिस तहसील में तैनात हैं, वहीं निवास करें।तहसील राजस्व प्रशासन के अंतर्गत सौंपी गई जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी तरह हो, यह सुनिश्चित करना संबंधित जिलाधिकारी व मंडलायुक्तगण का प्राथमिक दायित्व है। संबंधित जिलाधिकारी व मंडलायुक्तगण यह सुनिश्चित करेंगे कि संबंधित तहसीलदार व उपजिलाधिकारी जिस तहसील में तैनात किए गए हैं,

वहीं निवास करें। सभी जिलाधिकारी ईमेल आईडी पर 7 दिन के अंदर इस आशय का सर्टिफिकेट उपलब्ध कराएंगे। वहीं संबंधित मंडलायुक्त एवं शासन स्तर से इस विषय का आकस्मिक निरीक्षण व जांच भी की जाएगी।

संबंधित तहसीलदार व उपजिलाधिकारी यदि तहसील में निवासरत नहीं पाए गए तो उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही संबंधित जिलाधिकारी का भी उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा। इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

सहयोगियों को खुश करके पीएम मोदी अपना शासन तो बचा सकते हैं, लेकिन स्टालिन ने कसा पीएम मोदी पर तंज

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने बुधवार को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को चेतावनी दी कि यदि वह अपनी राजनीतिक पसंद और नापसंद के अनुसार सरकार चलाएंगे तो उन्हें अलग-थलग कर दिया जाएगा। बिहार और आंध्र प्रदेश को बजटीय आवंटन को लेकर पीएम पर हमला करते हुए स्टालिन ने एक्स पर लिखा कि अपने सहयोगियों को खुश करके पीएम मोदी अपना शासन तो बचा सकते हैं, लेकिन देश को नहीं। यह हमला विपक्ष द्वारा राज्यसभा में बहिर्गमन करने के कुछ घंटों बाद आया, जिसमें दावा किया गया कि बजट में केंद्र द्वारा अन्य राज्यों के साथ भेदभाव किया गया है

एमके स्टालिन ने पीएम मोदी पर उन लोगों का बदला लेने का आरोप लगाया जिन्होंने लोकसभा चुनाव में आपको हराया। भारत गठबंधन के सांसदों ने केंद्रीय वित्तीय रिपोर्ट में कई राज्यों को शामिल न किए जाने के विरोध में विरोध प्रदर्शन किया है। माननीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी आपने कहा था चुनाव खत्म हो गया है, अब हमें देश के बारे में सोचना होगा। उन्होंने एक्स पर लिखा कि लेकिन कल का सक्क्ह्स्त्रद्द्र्ह्2024 आपके शासन को बचाएंगे, भारत को नहीं! आम तौर पर उन लोगों का बदला लेने पर आमादा न हों जिन्होंने आपको अभी तक हराया है।

इस बीच, डीएमके सांसद दयानिधि मारन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एमके स्टालिन का अनुसरण करना चाहिए और उन लोगों के लिए काम करना चाहिए जिन्होंने उन्हें वोट नहीं दिया। मुझे लगता है कि समय आ गया है कि प्रधानमंत्री को हमारे मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से कुछ अच्छी सलाह लेनी चाहिए और उनका अनुसरण करना चाहिए। जब एमके स्टालिन तमिलनाडु के सीएम बने तो उन्होंने कहा- मैं न सिर्फ उन लोगों के लिए काम करूंगा जिन्होंने मुझे वोट दिया बल्कि उन लोगों के लिए भी काम करूंगा जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया, ये मेरा कर्तव्य है।

मुझे मत सिखाओ, बल्कि मेरे से सीख लो, बांग्लादेशियों को शरण देने वाले मुद्दे पर विदेश मंत्रालय को ममता की नसीहत

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हिंसा प्रभावित बांग्लादेश के शरणार्थियों को आश्रय देने की उनकी टिप्पणी पर आपत्ति जताने के लिए विदेश मंत्रालय (एमईए) पर पलटवार किया। बनर्जी ने कहा कि मैं संघीय ढांचे को अच्छी तरह से जानती हूं। मैं सात बार सांसद रही, मैं दो बार केंद्रीय मंत्री रही। मैं विदेश मंत्रालय की नीति को किसी और से बेहतर जानती हूं। उन्हें मुझे सबक नहीं सिखाना चाहिए। उन्हें इससे सीखना चाहिए। नौकरी में आरक्षण के विरोध को लेकर बांग्लादेश में हुई हिंसक झड़पों के बाद ममता बनर्जी ने संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव के तहत बांग्लादेशी शरणार्थियों को आश्रय प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता के बारे में बात की थी। उनकी टिप्पणी कोलकाता में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान आई, जहां उन्होंने हिंसा से प्रभावित लोगों की मदद करने की इच्छा व्यक्त की।

उन्होंने तृणमूल कांग्रेस की 'शहीद दिवस' रैली में कहा कि अगर असहाय लोग बंगाल के दरवाजे पर दस्तक देंगे तो हम निश्चित रूप से उन्हें आश्रय देंगे। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने बनर्जी की टिप्पणियों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए राजनयिक चैनलों के माध्यम से कहा कि उनकी टिप्पणियां भ्रम पैदा कर सकती हैं और जनता को गुमराह कर सकती हैं। विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की कि उसे ममता बनर्जी की टिप्पणी पर ढाका से एक लिखित आपत्ति मिली है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने कहा कि विदेशी संबंधों से जुड़े मामले केंद्र सरकार का विशेषाधिकार है।

जयसवाल ने कहा कि हमारे संविधान की सातवीं अनुसूची ङ्क सूची एक ङ्क संघ सूची ङ्क आइटम 10 के तहत, विदेशी मामलों का संचालन और सभी मामले जो संघ को किसी विदेशी देश के साथ संबंध में लाते हैं, केंद्र सरकार का एकमात्र विशेषाधिकार है।

अग्निवीरों को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला, यूपी पुलिस और पीएसी में मिलेगा आरक्षण

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार (26 जुलाई) को घोषणा की कि राज्य अग्निवीरों को यूपी पुलिस और पीएसी में आरक्षण प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि अग्निवीर जब अपनी सेवा के बाद वापस आएंगे, उत्तर प्रदेश सरकार पुलिस सेवा में, पीएसी में इन नौजवानों को प्राथमिकता के आधार पर समायोजन की सुविधा देगी। उनके लिए एक निश्चित आरक्षण की सुविधा उत्तर प्रदेश पुलिस में उपलब्ध कराएंगे।अपने बयान में उन्होंने कहा कि प्रगति और समृद्धि के नए प्रतिमान स्थापित करने के लिए समय-समय पर किए गए सुधार किसी भी देश और समाज के लिए आवश्यक होते हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में हमारी अर्थव्यवस्था को सम्मानजनक स्थान दिलाने और भारत को पांचवीं सबसे बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के लिए पिछले 10 वर्षों में कई कदम उठाए गए हैं और हर क्षेत्र में सुधार किए गए हैं।योगी ने आगे बताया कि हमें राष्ट्रीय सुरक्षा को समान महत्व देने की आवश्यकता है। सशस्त्र बल भी इस सुधार के साथ आगे बढ़े हैं।

मटन बताकर बेचा जा रहा कुत्ते का मीट, आरोपों से मचा हड़कंप

जांच के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने जांच के लिए भेजा सैंपल

बेंगलुरु- जयपुर से करीब तीन टन वजनी मांस की खेप बेंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन पहुंची। 150 कार्टन मांस मिलने से रेलवे अधिकारियों में हड़कंप मच गया। गौरक्षक पुनीत केरेहल्ली के अनुसार, शहर में कुत्ते का मांस आयात किया गया था। हालांकि, मांस का ऑर्डर देने वाले मीट डीलर अब्दुल रज्जाक ने इस आरोप को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि खेप कानूनी तौर पर मंगवाई गई थी और यह कुत्ते का मांस नहीं बल्कि भेड़ का मांस है।मीट व्यापारी ने कहा, हमारे पास इसे साबित करने के लिए कानूनी दस्तावेज हैं। जिस जानवर का वध किया गया, उसकी पूंछ देखी जा सकती है। यह भेड़ का मांस है, कुत्ता नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि केरेहल्ली झूठे आरोप लगाकर पैसा कमाना चाहता था। हंगामे के चलते वहां बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए और स्थिति को देखते हुए पुलिस को तैनात किया गया। मामले की आगे की जांच जारी है।

शुक्रवार शाम को केएसआर रेलवे स्टेशन पर उस समय अफरा-तफरी मच गई जब हिंदूवादी समूहों ने आरोप लगाया कि एक विक्रेता मटन के रूप में कुत्ते का मांस सप्लाई कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि जयपुर से जयपुर-मैसूर एक्सप्रेस के जरिए मांस के कार्टन लाए गए थे। हालांकि, विक्रेता ने दावा किया कि यह मटन है और वह पिछले 12 सालों से इस धंधे में शामिल है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी मौके पर पहुंचे

इस बीच, खाद्य सुरक्षा अधिकारी मौके पर पहुंचे और प्रयोगशाला जांच के लिए मांस के नमूने एकत्र किए और पता लगाया कि किस जानवर का मांस ले जाया जा रहा था। आयुक्त ने कहा, फ्रनिरीक्षण के दौरान, यह पाया गया कि राजस्थान से ट्रेन के जरिए आए पार्सल को स्टेशन के बाहरी परिसर में एक परिवहन वाहन में लोड किया जा रहा था। 90 पार्सल थे और जांच करने पर पार्सल में जानवरों का मांस पाया गया। नमूने एकत्र किए गए और जानवरों की प्रजातियों के विश्लेषण के लिए खाद्य प्रयोगशाला में भेजे गए।

सख्त कानूनी कार्रवाई

आयुक्त ने यह भी वादा किया कि अगर किसी अन्य मांस को मिलाने का कोई मामला पाया जाता है तो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा,विश्लेषण रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पार्सल भेजने वालों और प्राप्तकर्ताओं के लाइसेंस के बारे में विस्तृत जानकारी एकत्र की जा रही है। यदि कोई विसंगति पाई जाती है, तो कानून के अनुसार आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। इस बीच, इसने बेंगलुरु के निवासियों और मांस प्रेमियों के बीच दहशत पैदा कर दी है। एक एक्स पोस्ट में, इंफोसिस के पूर्व सीएफओ मोहनदास पई ने लिखा, यह चौंकाने वाला है। हमारी सरकार कब कार्रवाई करेगी?

मोदी सरकार के पिटारे से किसको क्या मिला, 2024 की वो 10 बड़ी बातें

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज बजट 2024 पेश किया। यह उनकी लगातार सातवीं बजट प्रस्तुति है, इससे पहले 2024 के लोकसभा चुनावों के कारण अंतरिम बजट पेश किया गया था, जिसमें कोई महत्वपूर्ण घोषणा नहीं हुई थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा अपना लगातार सातवां बजट पेश करने के कुछ घंटों बाद, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि बजट 2024 नव-मध्यम वर्ग, गरीबों, गांवों और किसानों को सशक्त बनाता है। राष्ट्र को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने यह भी कहा कि बजट युवाओं के लिए असीमित अवसर लाएगा।

बजट की 10 बड़ी बातें

वित्त वर्ष 2024-25 के आम बजट में शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बजट पेश करते हुए कहा कि इसमें रोजगार, कौशल विकास, एमएसएमई और मध्यम वर्ग पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है।

सरकार ने मंगलवार को कहा कि वह रोजगार से जुड़ी तीन योजनाएं शुरू करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार नौकरी बाजार में प्रवेश करने वाले 30 लाख युवाओं को एक महीने का पीएफ (भविष्य निधि) योगदान देकर प्रोत्साहन देगी। उन्होंने घोषणा की कि कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए देश में कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास स्थापित किए जाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार जलवायु-अनुकूल बीज विकसित करने के लिए निजी क्षेत्र, क्षेत्र विशेषज्ञों और अन्य को धन उपलब्ध कराएगी। पहले से ही मौजूद योजना ङ्क मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी) का लक्ष्य प्रत्येक परिवार के कम से कम एक सदस्य को एक वित्त वर्ष में 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराना है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को केंद्रीय बजट 2024-25 में अर्थव्यवस्था में पर्याप्त अवसर उत्पन्न करने के लिए नौ प्राथमिकताओं की घोषणा की। इन नौ प्राथमिकताओं में उत्पादकता, रोजगार, सामाजिक न्याय, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, बुनियादी ढांचा, नवाचार और सुधार शामिल है।

सरकार ने मंगलवार को अगले पांच वर्षों में 20 लाख युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए एक नई केंद्र प्रायोजित योजना की घोषणा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2024-25 में इसकी घोषणा की। वहीं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा दोगुनी यानी 20 लाख रुपये की जाएगी।

केंद्र ने मंगलवार को बिहार में विभिन्न सड़क परियोजनाओं के लिए 26,000 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव रखा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 के अपने बजट में कहा कि केंद्र सरकार बहुपक्षीय विकास एजेंसियों की सहायता के माध्यम से बिहार को वित्तीय सहायता की व्यवस्था करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार बिहार में हवाईअड्डे, मेडिकल कॉलेज और खेल संबंधी बुनियादी ढांचा भी स्थापित करेगी। सरकार ने मंगलवार को आंध्र प्रदेश के विकास के लिए कई उपायों की घोषणा की। इसमें राज्य की राजधानी के विकास के लिए चालू वित्त वर्ष और भविष्य के वर्षों में 15,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था करना भी शामिल है। राज्यों को उनके बुनियादी ढांचे के विकास में मदद के लिए सरकार दीर्घकालिक आधार पर 1.5 लाख करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराएगी।

सरकार ने मंगलवार को घोषणा की कि वह देश के पूर्वोत्तर राज्यों में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) की 100 शाखाएं स्थापित करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट में इसकी घोषणा की। आईपीपीबी में वर्तमान में करोड़ों खाते हैं और यह लाखों शाखाओं के जरिये संचालित किए जाते हैं।

वत्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को स्टार्टअप्स में सभी वर्ग के निवेशकों के लिए 'एंजल' कर समाप्त करने की घोषणा की। अपने बजट भाषण में उन्होंने ई-कॉमर्स कंपनियों तथा दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ के संदर्भ में कुछ वित्तीय साधनों के लिए कर दरों में विभिन्न बदलावों की भी घोषणा की।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को सोने एवं चांदी पर बुनियादी सीमा शुल्क को घटाकर छह प्रतिशत और प्लैटिनम पर 6.4 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा। सीतारमण ने लोकसभा में वित्त वर्ष 2024-25 का बजट पेश करते हुए यह घोषणा की। सोने, चांदी और प्लैटिनम के मूल सीमा शुल्क में कटौती रत्न एवं आभूषण उद्योग की लंबे समय से लंबित मांग रही है। सरकार ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट में मोबाइल फोन, चार्जर और हैंडसेट के विनिर्माण में इस्तेमाल होने वाले कुछ उपकरणों पर आयात शुल्क में कटौती का प्रस्ताव रखा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में वित्त वर्ष 2024-25 का बजट पेश करते हुए कहा कि पिछले छह वर्षों में मोबाइल फोन के घरेलू उत्पादन में तीन गुना वृद्धि हुई है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को आयकर प्रावधानों में कुछ बदलावों की घोषणा करते हुए मध्यम वर्ग और नौकरीपेशा लोगों को राहत दी। मानक कटौती को 50 प्रतिशत बढ़ाकर 75,000 रुपये करने और नई कर व्यवस्था के तहत कर स्लैब में बदलाव का प्रस्ताव बजट में रखा गया। वित्त मंत्री की इन घोषणाओं को नौकरीपेशा लोगों के हाथ में कुछ और पैसा देने की कोशिश माना जा रहा है। इससे खपत को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। प्रस्ताव के मुताबिक, तीन से सात लाख रुपये की आय पर पांच प्रतिशत, सात से 10 लाख रुपये की आय पर 10 प्रतिशत और 10-12 लाख रुपये की आय पर 15 प्रतिशत कर लगेगा। हालांकि, 12-15 लाख रुपये की आय पर 20 प्रतिशत और 15 लाख रुपये से अधिक की आय पर पहले की तरह 30 प्रतिशत कर लगता रहेगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को बच्चों के लिए नई पेंशन योजना 'वात्सल्य' शुरू करने की घोषणा की। वित्त मंत्री ने संसद में 2024-25 का बजट पेश करते हुए कहा कि इस पेंशन योजना में माता-पिता और अभिभावक अंशदान करेंगे। बच्चे के वयस्क होने पर, इस योजना को सहज रूप से एक सामान्य एनपीएस खाते में बदला जा सकेगा।

राहुल गांधी तो खटाखट पैसे नहीं दे पाए, हेमंत सोरेन के झारखंड में 45 लाख महिलाओं के खाते में 1000 रुपये 'फटाफट'

लोकसभा चुनाव 2024 में नेताओं की तरफ से अजीबोगरीब बयान खूब देखने सुनने को मिले। राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार केक दौरान खटाखट शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने गरीबों के खाते में एक-एक लाख रुपये डालकर खटाखट गरीबी खत्म करने की बात कही थी। राहुल गांधी न सत्ता में आए और नही गरीबी खत्म करने के दावे के साथ एक एक लाख रुपये अकाउंट में आने की बात सच हो पाई। लेकिन झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने इससे संबंधित एक फैसला लिया है जिससे हर महीने 45 लाख महिलाओं के एकाउंट में 1000 रुपये टकाटक जरूर आने लग जाएंगे। दरअसल, झारखंड के

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में सोरेन सरकार ने 30 एजेंडों पर मुहर लगी। 21-50 साल की महिलाओं को हर महीने मुख्यमंत्री बहन बेटी मई-कुई स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना के संशोधन को स्वीकृति दी गई है और इसके तहत 1000 रुपये की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी।

45 लाख महिलाओं के एकाउंट में 1000 रुपये

झारखंड मंत्रिमंडल ने राज्य की 45 लाख महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक महत्वाकांक्षी वित्तीय सहायता योजना को मंजूरी दी थी। 'मुख्यमंत्री बहन बेटी स्व-सहायता प्रोत्साहन योजना' के तहत प्रत्येक महिला को 1,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। राज्य सरकार इस पहल के लिए सालाना 5,500 करोड़ रुपये वहन करेगी। यह योजना 21 से 50 वर्ष की आयु की महिलाओं के लिए है। आयकरदाता, सरकारी कर्मचारी, ईपीएफ धारक और कुछ अन्य श्रेणियों को इस योजना के लाभ से बाहर रखा गया है।

किसे मिलेगा लाभ?

झारखंड मंत्रिमंडल ने जनवरी में 50 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं, आदिवासियों और दलितों को वृद्धावस्था पेंशन योजना में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इससे पहले इस योजना का लाभ केवल 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को ही मिलता था, जिसके तहत प्रत्येक लाभार्थी को प्रति माह 1,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं।

एक अन्य फैसले में झारखंड मंत्रिमंडल ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए मुफ्त बिजली की पात्रता 125 यूनिट प्रति माह से बढ़ाकर 200 यूनिट प्रति माह करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। मुफ्त बिजली योजना पर दादेल ने कहा कि सरकार इसके लिए प्रति माह लगभग 21.7 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ वहन करेगी। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से लगभग 41.4 लाख उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा।

दुस्साहस: कचहरी में असलहों समेत घुसकर वकील और पैरोकार पर हमला !

- इरफान गैंग के कुख्यात भूमाफिया ने रजिस्ट्री कार्यालय में घुसकर सरेआम की वारदात
- बिल्डर को रजिस्ट्री कराने से रोकना चाहता था आरोपी माफिया केके कलीम खान

बीपीएस न्यूज

कानपुर। सीएम योगी की सख्ती के बावजूद, कानपुर महानगर में पुलिसिया ढिलाई जारी है। इसके चलते गुंडे-माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। हालिया घटना में जेल में बंद पूर्व विधायक इरफान सोलंकी गैंग के कुख्यात भूमाफिया साथी, पेंचबाग निवासी केके उर्फ कलीम खान ने अपने गैंग के साथ दुस्साहसिक वारदात को अंजाम दे डाला। केके ने कचहरी परिसर में बने रजिस्ट्री कार्यालय में, हथियारबंद गुर्गों संग घुसकर बिल्डर और उसके वकील पर जानलेवा हमला कर दिया। मुवक्किल को बचा रहे उसके वकील विकास कुमार गुप्ता को सरेआम पीटा। केके और उसके गुर्गों ने कथित तौर पर जान से मारने की नीयत से वकील और मुवक्किल को रजिस्ट्री कार्यालय परिसर में ही दबोच लिया था।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार केके और गैंग बिल्डर और वकील को जमीन की रजिस्ट्री कराने पर जान से मार डालने की धमकी दे रहे थे। दुस्साहसिक वारदात देख कर वकीलों ने हमलावरों को पकड़ने के लिए दौड़ा लिया। इसपर शातिर केके उर्फ कलीम खान गैंग समेत भाग निकला। लेकिन हमले में शामिल गैंग के कथित सदस्य दीपक पांडे अधिवक्ताओं के हत्थे चढ़ गया। कचहरी परिसर चौकी पुलिस ने उसको हिरासत में लिया, पर बाद में दबाव पड़ने पर छोड़ भी दिया गया। केके गैंग के हमले में वकील के हाथ पर जख्म हो गया। बिल्डर मुवक्किल मो. अकबर को भी हमले में चोटें आई हैं। पीड़ित वकील विकास गुप्ता ने थाना कोतवाली में हमलावर भूमाफिया केके उर्फ कलीम खान के खिलाफ पांच संगीन धारों में एफआईआर दर्ज करवाई है। उनके अनुसार केके उनके मुवक्किल को जमीन की रजिस्ट्री करने से रोकना चाहता था। बीते शनिवार को हुई इस वारदात के बाद अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं होने से अधिवक्ताओं में आक्रोश है। पकड़े गए एक हमलावर को छोड़ दिए जाने को लेकर भी वकीलों में गुस्सा है।

आखिर कौन है शातिर केके उर्फ कलीम खान !

पीड़ित अधिवक्ता विकास गुप्ता ने बताया कि शातिर भूमाफिया केके उर्फ कलीम खान भूमाफियागीरी में लिप्त इरफान सोलंकी गैंग का सदस्य है। वो इरफान के लिया विवादित जमीनों पर कब्जे और खरीद बेंच का काम करता है। पीड़ित एडवोकेट विकास और बिल्डर मो. अकबर के अनुसार केके उर्फ कलीम खान पर बेकनगंज, चमनगंज और जाजमऊ आदि थानों में हत्या, हत्या के प्रयास, जमीनों पर कब्जे, सार्वजनिक हिंसा, जानमाल की धमकी देने आदि संगीन धाराओं में कई मुकदमे दर्ज हैं। इनमें से कई मुकदमों को इस शातिर ने किसी तरह खत्म करवा लिया है, तो वहीं कई मुकदमे जारी हैं। कचहरी परिसर में घटित दुस्साहसिक वारदात से आक्रोशित वकीलों ने सुरक्षा बढ़ाने, हथियारों को सख्ती से वर्जित करने और वकीलों की सुरक्षा के लिए बने एक्ट को लागू करने की मांग की है।

पुलिस से बचने को मीडिया का चोला ओढ़ा !

अधिवक्ता विकास के अनुसार पुलिस और मीडिया से बचने के लिए शातिर केके कलीम खान ने मीडिया का चोला पहनने का प्रयास किया है। खुद को एक नामी अखबार का शहर प्रबंधक बताता है। अधिवक्ता और पीड़ित बिल्डर के अनुसार उक्त अखबार के मालिकान से लिखित में केके की अपराधिक रिकॉर्ड देकर आपत्ति दर्ज करवाएंगे। बताया गया कि शातिर केके ने अपने घर और एक कब्जा की बिल्डिंग पर भी उक्त अखबार का एक बोर्ड लगवाकर खुद को प्रबंधक लिखवा रखा है।

फल विज्ञान और फ्लोरी कल्चर के संयुक्त तत्वाधान में दो दिवसीय प्रशिक्षण का शुभारंभ

कानपुर । चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विवि के फल विज्ञान विभाग तथा फ्लोरी कल्चर सोसायटी के संयुक्त तत्वाधान में गुरुवार को दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। प्रशिक्षण का शुभारंभ विवि के कुलपति डॉ आनंद कुमार सिंह एवं समिति की अध्यक्ष उषा झुनझुनवाला, सचिव राजश्री डालमिया, सीएसजेएमयू के डॉ हिमांशु त्रिवेदी, डॉ आर पी सिंह पूर्व विभागाध्यक्ष उद्यान विज्ञान की उपस्थिति में किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन प्रोफेसर वी के त्रिपाठी, विभागाध्यक्ष उद्यान विज्ञान द्वारा किया गया। प्रशिक्षण के प्रथम दिन उद्घाटन के अवसर पर विवि के कुलपति डॉ आनंद कुमार सिंह ने कहा कि हमको अपने घर में पर्यावरण को बचाते हुए अपने घर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए विभिन्न शोभाकारी पौधों को रोपित करने के साथ उनका उचित प्रबंध करना अति आवश्यक है। उन्होंने ऋतु के अनुसार सभी फलों और सब्जियों का प्रतिदिन सेवन करने की सलाह दी। जिससे हम स्वस्थ रहते हुए अपने अंदर प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर सकते हैं और संभव हो सके तो सब्जियां अपने घर में ही उगाकर सेवन में ले तो ज्यादा अच्छा रहता है। इस अवसर डॉ वी के त्रिपाठी, विभागाध्यक्ष उद्यान विज्ञान ने ऋतु के अनुसार घर में उगाये जाने वाले शोभाकारी पौधों के प्रबंधन, उनके उत्पादन की विभिन्न बारिकियों पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पौधों को किस प्रकार से उत्पादन और घर में किस प्रकार और कहा किस पौधे को रोपित करके, घर पर ही अपने स्वयं के पौधे कैसे तैयार कर सकते हैं। डॉ हिमांशु त्रिवेदी ने पौधों से बोनसाई बनाने की विभिन्न तरीकों और समय के बारे में जानकारी दी। डॉ आर पी सिंह ने अपने-अपने बंगले में लॉन को कैसे रोपित कर सुंदर बनाएं, के बारे में जानकारी दें। डॉ राजीव ने पोषण वाटिका को बनाने, सब्जियों को उगाने की तकनीक के बारे में विशेष जानकारी दी। स्वागत भाषण में समिति की अध्यक्ष उषा झुनझुनवाला ने बताया कि हम सभी अपने-अपने घरों/बंगलो पर स्वयं से तथा अपने सहयोगियों की मदद से विभिन्न पौधों को रोपित कर शहर में पर्यावरण के प्रति मुहिम चलाते रहते हैं। संस्था की सचिव राजश्री डालमिया ने बताया कि हम सब 2007 में स्थापित की गई इस संस्था के द्वारा शहर में पर्यावरण और सुन्दरता से संबंधित विभिन्न कार्यक्रम करते रहते हैं। कार्यक्रम के अंत में सभी का धन्यवाद ज्ञापन संस्था के सदस्य श्री मनोज गुप्ता जी ने किया। इस कार्यक्रम में आभा अग्रवाल, कंचन गर्ग सहित संस्था के 30 सदस्यों ने प्रतिभाग किया। इस अवसर पर विभाग के शिक्षक सहायक, शोध छात्र एवं परास्नातक छात्र एवं छात्राएं भी उपस्थित रहे।

विश्व ओआरएस सप्ताह में लगा नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविर

तुलसी हास्पिटल में डॉक्टर डायरिया संबंधी बच्चों को सहुलियत के साथ देखेंगें

बीपीएस न्यूज

कानपुर। सिविल लाइंस स्थित तुलसी हॉस्पिटल इंडिया लिमिटेड ने विश्व ओआरएस सप्ताह मनाने का फैसला लिया है। जिसके तहत 25 से 31 जुलाई तक नि:शुल्क स्वास्थ्य कैंप लगाया जा रहा है। तुलसी हॉस्पिटल के एमडी शेखर गुप्ता ने बताया कि दोपहर 12 से 1 बजे तक ओपीडी में मुफ्त में मरीज देखे जाएंगे। इसके साथ ही दवाओं और जांचों मैं विशेष छूट भी दी जा रही है। शिविर का उद्घाटन वरिष्ठ डॉक्टर वी एन त्रिपाठी ने किया। डॉक्टरत्रिपाठी ने कहा कि इस मौसम में बच्चो को लूज मोसन की समस्या ज्यादा होती है। इसको देखते हुए बच्चो के लिए शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर में आज 40 बच्चो को ओपीडी में देखा गया तथा उन्हें दवा दी गई। गायनी सर्जन डॉक्टर चंचल गुप्ता ने नवजात बच्चों को मां के दूध की अहमियत बताई की अगर छह माह तक मां अपने बच्चे को अपना दूध पिलायें और सौ बिमारियों से बचायें कार्यक्रम में तुलसी हॉस्पिटल के

सीएमडी अमर शंकर गुप्ता, डॉक्टर विवेक माहेश्वरी, डॉक्टर चंचल गुप्ता, डॉक्टर अनुराग केसरवानी, डॉक्टर अमितेश यादव, डॉक्टर नीता अग्रवाल, डॉक्टर कीर्ति गुप्ता आदि मौजूद रहे।

एक पेड़ माँ के नाम की थीम पर किया गया वृक्षारोपण

कानपुर। दयानंद गर्ल्स पी जी महाविद्यालय में कारगिल विजय दिवस 24-26 जुलाई के अनवरत एक वृक्ष एक कैडेट् के अंतर्गत वृहद वृक्षारोपण आयोजित किया गया। इस अवसर पर एनसीसी कैडेट्स द्वारा एक पेड़ मां के नाम थीम के आधार पर वृक्षारोपण किया गया। कार्यक्रम में महाविद्यालय की प्राचार्या प्रो वंदना निगम, स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम निदेशिका प्रो अर्चना वर्मा, एएनओ प्रो.(कै) शुभ्रा राजपूत और डा मनीषी पाण्डेय तथा 34 एनसीसी कैडेट्स ने सहभागिता की। इस दौरान नीम, जामुन, पीपल, अमरूद,कनेर, बरगद, अशोक आदि के पौधों का रोपण किया गया। प्रो शुभ्रा राजपूत ने बताया की पेड़ लंबे समय तक ऑक्सीजन प्रदान करके, वायु की गुणवत्ता में सुधार करके, जलवायु सुधार करके, जल संरक्षण करके, मिट्टी को संरक्षित करके और वन्यजीवों का समर्थन करके अपने पर्यावरण में योगदान करते हैं।।

यातायात सिस्टम में सुधार के लिये ट्राफिक दोस्त अभियान का शुभारंभ

बीपीएस न्यूज

कानपुर। यातायात व्यवस्था को और बेहतर से बेहतर बनाने के लिये पुलिस आयुक्त अखिल कुमार के दिशा निर्देशन में %ट्राफिक दोस्त% के नाम से एक महत्वाकांक्षी अभियान का गुरुवार को पुलिस कार्यालय में औपचारिक शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर अपर पुलिस आयुक्त कानून-व्यवस्था एवं यातायात हरीश चंदर व पुलिस उपायुक्त आरती सिंह ने ट्राफिक दोस्त% अभियान के बारे में मीडिया को अवगत कराया। अपर पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था एवं यातायात हरीश चंदर व पुलिस उपायुक्त आरती सिंह ने सयुक्त रुप से बताया कि ट्राफिक दोस्त अभियान दो चरणों में होगा। पहले चरण में शहर की आम से यातायात सुधार संबंधी समस्या और समाधान के बारे में सुझाव मांगे जायेंगे जबकि दूसरे चरण में जनमानस से मिले सुझाव और समस्याओं का निस्तारण कराये जाने के प्रयास किये जायेंगे। उन्होंने बताया कि मोबाइल फोन कॉल के अलावा सभी सोशल मीडिया प्लेटफार्म के माध्यम से लोग यातायात संबंधी समस्या व समाधान के बारे में अपने सुझाव साझा कर सकेंगे। ट्वीटर एक्स कॉम, फेसबुक, इंस्टाग्राम व मेल के माध्यम से समस्या व सुझावों को बताया जा सकेगा। यातायात पुलिस की ओर से हेल्प लाइन नंबर 93051 04387 जारी किया गया है। अपर पुलिस आयुक्त कानून-व्यवस्था एवं यातायात हरीश चंदर ने बताया कि यातायात संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिये मिड, शार्ट व लांग टर्म प्लान तैयार किये जायेंगे। ट्राफिक दोस्त अभियान का पहला चरण 10 से 15 दिन का होगा। इसके बाद अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत की जायेगी। अभियान के तहत एक विजन डाकूमेंट बनाये जाने की बात कही।

बंदियों के मानसिक उत्थान के लिये कारागार में शिविर का आयोजन

बीपीएस न्यूज

कानपुर। जिला कारागार,कानपुर नगर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा स्वयंसेवी संस्था अपराध मुक्त सामाजिक चिकित्सा समिति, कानपुर नगर के माध्यम से एक शिविर का आयोजन किया गया,जिसमें क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट-डॉ0 आराधना गुप्ता तथा उनकी टीम के अन्य सहयोगी पवन मिश्रा,दीपक कुमार के द्वारा बन्दियों की काउंसलिंग की गयी। जेल अधीक्षक डॉ0 बी0डी0 पाण्डेय द्वारा बताया गया कि उक्त कार्यक्रम की अध्यक्षता अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कानपुर नगर शुभी गुप्ता द्वारा की गयी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शुभी गुप्ता द्वारा बन्दियों के मानसिक उत्थान हेतु कारागार में समय-समय पर बन्दियों की काउंसलिंग कराये जाने की आवश्यकता पर बल दिया ताकि बन्दियों को अवसाद से बचाया जा सके। मनोवैज्ञानिक डॉ0 आराधना गुप्ता द्वारा बन्दियों को अवसाद से बचने के कुछ सुझाव दिये गये, जिनमें सबसे प्रमुख अपने को किसी न किसी सकरात्मक क्रियाकलाप में नियोजित रखना जैसे-खेलकूद, योगाभ्यास,ड्राइंग, पेन्टिग इत्यादि, ताकि उनका मस्तिष्क सही दिशा में सोच-विचार कर सके एवं बन्दियों को तनावमुक्त बनाये रखने के लिये परिश्रम करने बल दिया तथा अकेलेपन/अवसाद से बचने के लियेज्यादा सेज्यादा लोगों से मिलते-जुलते रहें। जेल अधीक्षक द्वारा मनोवैज्ञानिक डॉ0 आराधना गुप्ता एवं उनकी टीम द्वारा कारागार में बन्दियों के मानसिक उत्थान हेतु आयोजित उक्त शिविर के प्रति आभार व्यक्त करते हुये भविष्य में भी इस तरह के शिविर का आयोजन किये जाने का अनुरोध किया गया। इस अवसर पर स्वयंसेवी संस्था अपराध मुक्त सामाजिक चिकित्सा समिति के चैयरमैन आशुतोष बाजपेई, महासचिव योगेश बाजपेई,सचिव अंकुश व राजेश तथा कारागार से चिकित्साधिकारी-डॉ0 समीर नारायण,जेलर मनीष कुमार,फार्मासिस्ट इन्द्रजीत सिंह राना,डिप्टी जेलर अरूण कुमार सिंह,कमल चन्द्र,प्रेम नारायण उपस्थित रहे।

नवांगतुक नगर आयुक्त ने संभाला चार्ज, कैंप लगा हाउस टैक्स बिल की विसंगतियों को करेंगे दूर

बीपीएस न्यूज

कानपुर। गुरुवार को नगर आयुक्त का चार्ज सुधीर कुमार गहलोत ने संभाल लिया। उन्हें सीडीओ पद से रिलीव कर दिया गया है। नगर आयुक्त ने चार्ज संभालते ही अधिकारियों और महापौर के साथ बैठक की। नगर निगम और विकास कार्यों को समझा।

शहर की स्थितियों से पहले से ही वाकिफ नगर आयुक्त सुधीर कुमार ने कहा कि शहर में राजस्व वसूली, सफाई और अतिक्रमण पर फोकस रहेगा। उन्होंने कहा कि बारिश के दौरान जगह-जगह सड़कें खराब हो गई हैं। ऐसे में वह कानपुर में सड़कों का सर्वे कराकर उन्हें गड्ढामुक्त कराने का काम करेंगे। हाउस टैक्स में बिलिंग की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाएगा। हर जोन और वार्ड में कैंप लगाए जाएंगे। नगर आयुक्त ने बताया कि 500 करोड़ से रेवेन्यू को बढ़ाकर 700 करोड़ तक बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा पूरे शहर में सफाई व्यवस्था को और दुरुस्त किया जाएगा। वहीं शहर में धड़ल्ले से बन रहे फ्लैट्स के नामांतरण में आ रही मुश्किलों को दूर किया जायेगा। बारिश को देखते हुए जलभराव की समस्या का त्वरित निदान और एंटी लार्वा का छिड़काव व फॉगिंग का कार्य भी तेज किया जाएगा।

इसके अलावा उन्होंने राजस्व वसूली तेज करने और अतिक्रमण के खिलाफ अभियान छेड़ने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि सूरत जैसे छोटे शहर में राजस्व वसूली काफी बेहतर है, इसके अलावा कानपुर में जाम की सबसे बड़ी समस्या अतिक्रमण है, जिसे चिन्हित करने के साथ ही अभियान चलाया जाएगा। चार्ज लेने के बाद उन्होंने महापौर प्रमिला पांडेय से मुलाकात की।

पंचशील गेट पर लगी गौतम बुद्ध की प्रतिमा अराजक तत्वों ने की खंडित, लोगों में आक्रोश

बीपीएस न्यूज

कासगंज। साथ ही बुद्ध की खंडित प्रतिमा को बदलवाए जाने की मांग की। वहीं घटना की सूचना मिलते पटियाली सीओ और सुन्नगढी थानाध्यक्ष मौके पर पहुंच गए और गुस्साए ग्रामीणों को समझाया बुझाकर कार्रवाई का आश्वासन दिया।भीकमपुर गांव के बाहर पंचशील गेट बना हुआ है। गेट के ऊपर गौतम बुद्ध की प्रतिमा लगी हुई है। शनिवार की रात में अराजक तत्वों ने माहौल खराब करने के लिए प्रतिमा को खंडित कर दिया। इस मामले की जानकारी सुबह बुद्ध के अनुयायियों को हुई तो वह भारी संख्या में एकत्रित हो गए। उनका कहना था कि दूसरी बार पंचशील गेट से अराजक तत्वों ने छेड़छाड़ की है। पहले पंचशील गेट से झंडा उतार कर भगवा झंडा लगा दिया था। इस बार बुद्ध की प्रतिमा को

खंडित कर दिया।

सीओ थानाध्यक्ष पहुंचे मौके पर

पंचशील गेट पर गौतम बुद्ध की प्रतिमा खंडित करने की खबर पाकर सीओ राजकुमार पांडेय और थानाध्यक्ष सरिता तोमर भारी फोर्स के साथ मौके पहुंचे। आक्रोशित ग्रामीणों को समझाने बुझाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण अराजक तत्वों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े रहे। बाद में आरोपियों की गिरफ्तारी और खंडित प्रतिमा को बदलवाए जाने की मांग पर माने। तब जाकर ग्रामीणों का गुस्सा शांत हुआ। सीओ ने कहा कि अराजक तत्वों से सख्ती से निपटा जाएगा और कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

प्रथम दृष्टया देख कर ऐसा प्रतीत होता है कि गौतम बुद्ध की प्रतिमा सीमेंट से छुटकर जमीन पर गिरकर टूट गई है। फिर भी ये लोग तहरीर दें तो मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। -सरिता तोमर, थानाध्यक्ष, सुन्नगढी।

बेटी की बरामदगी के लिए भटक रही मां, दरोगा पर लगाया धमकाने का आरोप

बीपीएस न्यूज

रामपुर। किशोरी को भगा ले जाने में पटवाई पुलिस ने पीड़ित किशोरी की मां को धमका कर गुमशुदगी लिख दी। किशोरी की मां का आरोप है कि उसकी बेटी को थाना क्षेत्र के गांव का ही संजू पुत्र हरलाल 18 जून को भगा ले गया था। जिसका शिकायती पत्र किशोरी की मां ने पटवाई थाने पहुंचकर पटवाई थाना प्रभारी अमरनाथ वर्मा को सौंपा था। आरोपी के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की गुहार लगाई थी। जिसकी जांच दरोगा सुभाष चंद कर रहे थे। पीड़ित मां का आरोप है कि

दरोगा आए दिन हमें धमकाते हैं। कई बार थाने बुलाया।

आरोपी पूरा परिवार घर से फरार है। किशोरी की मां ने कहा, दरोगा बोल रहे थे कि तेरी लड़की ने शादी कर ली है। धमकाते हुए गुमशुदगी लिख ली। पीड़ित ने पांच जुलाई को पुलिस अधीक्षक से मिलकर अपनी बेटी की बरामदगी करने की मांग की। मां ने बताया कि पुलिस अधीक्षक ने आश्वासन दिया था कि बेटी को जल्द ही बरामद कर लिया जाएगा। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक और पटवाई पुलिस से गुहार लगाने पर भी मेरी बेटी को बरामद नहीं किया जा रहा है।थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी भांजी उसके पास ही रहती है और कक्षा 12 की छात्रा है। 25 जुलाई को वह बिलासपुर दवाई लेने गई थी फिर वापस नहीं लौटी। काफी तलाश करने के बाद जानकारी मिली कि थाना क्षेत्र के रायपुर गांव निवासी गौरव उसकी भांजी को बहला फुसला कर भगा ले गया है। भांजी को भगाने में उसके परिजन मुकेश, लौकीराम व राजकुमारी ने सहयोग किया है। पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर छात्रा की तलाश शुरू कर दी है। प्रभारी निरीक्षक ज्योति सिंह ने बताया कि छात्रा की तलाश को टीमों का गठन कर दिया गया है जल्दी ही आरोपियों को गिरफ्तार कर छात्रा को बरामद कर लिया जाएगा।

एमएलसी अरुण पाठक ने बीएसए को बताई शिक्षकों की समस्याएं

2 माह की समय सीमा में सभी समस्याओं के निस्तारण करने का बीएसए को दिया निर्देश

बीपीएस न्यूज

कानपुर देहात। दो माह के अंदर प्राथमिक शिक्षको को लेखा पर्ची ब्लॉक स्तर पर मिलनी शुरू हो जाएगी। उक्त बात का आश्वासन बीएसए व लेखाधिकारी ने सैकड़ो शिक्षको की मौजूदगी में स्नातक एमएलसी अरुण पाठक को दिया है। शुक्रवार को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत एमएलसी अरुण पाठक शिक्षको की समस्याओं के निस्तारण के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचे। जहां पहले से ही अपनी समस्याओं के निस्तारण के लिए मौजूद शिक्षको ने पाठक का स्वागत किया। इसके बाद बीएसए कार्यालय में एमएलसी अरुण पाठक की उपस्थित में बीएसए अजय मिश्रा, लेखाधिकारी आशुतोष त्रिपाठी के समक्ष बिंदुवार समस्याओं को रखा गया। सबसे ज्यादा समस्या चयन वेतन मान, अवशेष वेतन, वेतन वृद्धि की रही। इसके साथ ही एनपीएस, सेवा पुस्तिका, आवास भत्ता विसंगति से शिक्षको ने शिकायत रखी। जिसके बाद जिले में बेसिक शिक्षको को पटल के बाबुओं द्वारा खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से लेकर जिले स्तर तक शोषण करने की शिकायत शिक्षकों के द्वारा की गई। जिस को सुनकर एमएलसी अरुण पाठक ने गहरी नाराजगी जताई, साथ ही ऐसे बाबुओं को अपनी कार्य शैली में शीघ्र सुधार करने की चेतावनी दी। साथ ही बीएसए व लेखाधिकारी को निर्देश दिया कि जो समस्याएं दी गई है उन्हें एक सप्ताह में निस्तारित कर अवगत कराए। इस दौरान प्रमुख रूप विधायक प्रतिनिधि बाल जी शुक्ल, शिक्षक प्रतिनिधि अरुण दुबे, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के

जिला संगठन मंत्री अनंत त्रिवेदी महामंत्री पुनीता पालीवाल शैलेश त्रिपाठी, राजेश शुक्ला, संतोष पाठक, पुनीता पालीवाल, देवेंद्र तिवारी अमित कुमार तिवारी संजय त्रिपाठी ओम नारायण कटियार अर्चना कटियार, शालनी शर्मा, अनिरुद्ध सिंह अमित श्रीवास्तव, मुनींद्र गौतम, मंजीत सिंह, आशीष दीक्षित, प्रभात मिश्रा, विनय शुक्ला आदि मौजूद रहे।

बरेली : शाही के गौसगंज गांव में बवाल के 8 और आरोपी गिरफ्तार, भेजे गए जेल

बीपीएस न्यूज

बरेली/शाही। शाही के गांव गौसगंज में 19 जुलाई को हुए सांप्रदायिक बवाल के आठ और आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन्हें शनिवार को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। इससे पहले 35 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं।गौसगंज में 16 जुलाई को ताजिये निकालने के दौरान हिंदू और मुस्लिम पक्ष के लोगों में कहासुनी हुई थी। हिंदू पक्ष का आरोप है कि अगले दिन मुस्लिम पक्ष ने बैठक कर बवाल करने की योजना बनाई। आरोपी अब्दुल ने 19 जुलाई को एक महिला के चेहरे पर लेजर लाइट डालकर छेड़छाड़ की। इसका विरोध करने पर उसने 65 लोगों को इकट्ठा कर हिंदू पक्ष पर लाठी-डंडे और लोहे की रॉड से हमला कर दिया। इसमें पूर्व प्रधान के बेटे की मौत हो गई थी।पुलिस ने शनिवार को इस मामले में गौसगंज के यासीन उर्फ आसीन, उमर, निसार अली, रियासत अली, इसरार अहमद, नाजिम, बुंदन, बख्श और हासम को गिरफ्तार

किया। हालांकि अब्दुल के जिन दो बेटों पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया है, वे अभी पुलिस के हाथ नहीं आए हैं।पुलिस अधीक्षक दक्षिणी मानुष पारीक ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में एक नामजद था, बाकी सात के नाम विवेचना में सामने आए थे। बाकी आरोपियों को तलाश किया जा रहा है। इधर, शनिवार को भीम आर्मी के एक प्रतिनिधि मंडल ने पुलिस अधीक्षक दक्षिणी मानुष पारीक से मुलाकात कर मुस्लिम पक्ष के लोगों को निर्दोष बताया।

भ्रष्टाचार में लिप्त जिलों के थानो व चौकी पर डीजीपी नियंत्रण कक्ष की सीधी नजर

जन शिकायतों पर नहीं करते हैं प्रभावी कार्रवाई

बीपीएस न्यूज

लखनऊ। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के निर्देशन के अनुसार प्रदेश में कानून का जिला स्थापित करने कवायद तेज हुई है। लेकिन इसी कानून के राज्य से एक बड़ी खबर निकल कर आई है वह है भ्रष्टाचार पर नियंत्रण हाल ही में बलिया प्रकरण में पुलिस की पोल खुली है। जिससे पूरे प्रदेश में भृष्ट जिलो के थानों व चौकियों पर डीजीपी नियंत्रण कक्ष की सीधी नजर है। शुक्रवार को मिली जानकारी के मुताबिक, जिस प्रकार से डीजीपी नियंत्रण कक्ष की निगरानी से कानून एवं व्यवस्था में उल्लेखनीय सफलता मिली है। उसी को नया आयाम देते हुए भ्रष्टाचार पर नियंत्रण की भी निगरानी की जायेगी। जानकारी में बताया गया है कि यूपी— 112 के माध्यम से भ्रष्टाचार की शिकायतें भी प्राप्त होती हैं जिन्हें डीजीपी नियंत्रण कक्ष से जोड़कर अपर पुलिस महानिदेशक अपराध/लोक शिकायत/कानून व्यवस्था के माध्यम से उनकी समयबद्ध तरीके से समीक्षा की जाएगी और शिकायतकर्ता को स्थिति से अवगत भी कराया जाएगा।

ग्राम पंचायत से नगर पालिका में शामिल मोहल्ला, लेकिन नहीं बदले हालात

- कृष्णानगर मंडी समिति मोहल्ले में गलियों में जलभराव
- स्थानीय लोगों ने कहा कि जल भराव से कब मिलेगी निजात
- नगर पालिका के अधिकारियों की मनमानी

बीपीएस न्यूज

कानपुर देहात। नगर पालिका पुखरायां में कृष्णा नगर मंडी समिति नगर पालिका का हिस्सा हो गया है। जिससे अब वहां सारी सुविधाएं नगर पालिका के अधीन हो गई है।

इसके बाद भी यहां के लोगों का दुर्भाग्य साथ नही छोड़ रहा है।कृष्णा नगर मंडी समिति के नट मोहल्ले बस्ती जहां पर लगभग एक सैकंडा घर बने हुए हैं कई गलियां अभी भी कच्ची व पानी से भरी हुई है। गंदगी व कीचड़ होने के कारण छोटे-छोटे बच्चे महिलाएं निकल नहीं पा रहे हैं।

कृष्णा नगर मंडी समिति मोहल्ले के निवासी अरुण कुमार सुरेश दादा अजब सिंह नीतू अमरीश अनिल संगीता काजल शिलावती ने बताया कि लगभग 2 साल से गली में पानी भर रहा है। कच्ची गली होने के कारण थोड़ी सी बरसात में दलदल हो जाता है जिससे बूढ़े बुजुर्ग बच्चों व महिलाएं नहीं निकाल पाती है। कई बार नगर पालिका अधिकारी के यहां फरियाद भी लगे फिर भी ना तो कच्ची मिट्टी डालकर रास्ता सही की जा रही है और ना ही खड़ंजा डाला जा रहा है दलदल वाली गली से छोटे बच्चे भी होकर स्कूल को जाते हैं बच्चे अपने जूते हाथ में लेकर जब स्कूल पहुंच जाते हैं तो गंदगी से कीचड़ से पैर साफ कर कर विद्यालय पहुंचते हैं वापसी में भी यही हाल होता है छोटे-छोटे बच्चे महिलाएं परेशान गंदगी कीचड़ के कारण कीड़े भी हो रहे हैं बीमारी फैल रही है।

एक सैकड़ो महिलाओं व बच्चों ने जाकर नगर पालिका व उप जिलाधिकारी भोगनीपुर को आवेदन भी दिया लेकिन एक साल से अधिक समय हो गया गली में ना तो मिट्टी डाली जा रही ना खड़ंजा डाला जा रहा है इसे पूरी गली दलदल बनी है

परिषदीय स्कूलों के बच्चे अपनी माता के साथ रोपित करेंगे पौधा

प्रदेश के सभी परिषदीय स्कूलों में इको क्लब फार मिशन लाइफ का गठन किया जाएगा

बीपीएस न्यूज

लखनऊ। पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रदेश के सभी परिषदीय स्कूलों में %इको क्लब फार मिशन लाइफ का गठन किया जाएगा। इसके तहत 31 अगस्त तक स्कूली बच्चे अपनी माताओं के साथ स्कूल परिसर व सार्वजनिक स्थलों के अलावा अमृत सरोवरों के करीब पौधे रोपेंगे। हर पौधे की जियो टैगिंग होगी और उसे रोपने वाले बच्चे और उनकी माताओं के नाम लिखी तख्तियां भी लगेंगी। बढ़ते पौधों के साथ विद्यार्थी अपनी माता के साथ फोटो लेकर उसे सोशल मीडिया अथवा स्कूली मंच पर साझा कर सकेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के निर्देश पर 27 जुलाई से प्रदेश भर के स्कूलों में पौधरोपण का यह अभियान शुरू होगा। केंद्र सरकार के निर्देश पर राज्य सरकार एवं स्कूल शिक्षा महानिदेशक ने इस संबंध में प्रदेश के सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया है। निर्देश में कहा गया है कि सभी परिषदीय स्कूलों में इस क्लब का गठन किया जाएगा जिसके प्रभारी स्कूल के प्रधानाध्यापक होंगे जबकि सहायक अध्यापक या अध्यापिका इस क्लब की नोडल अधिकारी होंगे। एक छात्र या छात्रा को कैप्टन बनाया जाएगा जबकि प्रत्येक कक्षा में दो छात्र एवं दो छात्राओं को क्लब का समन्वयक बनाया जाएगा। इको क्लब फार मिशन लाइफ के लिए केंद्रीय शिक्षा एवं वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय आर्थिक सहायता प्रदान करेगा।

आज से ही शुरू हो जायेंगी गतिविधियां-इको क्लब फार मिशन लाइफ को पहले दिन से प्रभावी बनाने के लिए कल 27 जुलाई को सभी राजकीय प्राइमरी स्कूलों में ईको क्लब फॉर मिशन लाइफ डे मनाया जाएगा। इसमें शनिवार को छात्र-छात्राओं को पर्यावरण गतिविधियों में भाग लेने के लिए शिक्षकों की ओर से विद्यार्थियों को प्रेरित और प्रोत्साहित किया जाएगा। 27 जुलाई से 31 अगस्त तक पौधरोपण कार्यक्रम चलेगा। प्रत्येक परिषदीय प्राथमिक, कम्पोजिट, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को प्रत्येक विद्यालय को कम से कम 35 लगाना अनिवार्य होगा। बच्चे और उनकी माताएं साथ में पौधे रोपेंगे जिसका जियो टैगिंग किया जाएगा। प्रत्येक पौधे के साथ एक तख्ती लगाई जाएगी, जिस पर छात्र या छात्रा के अलावा उनकी माता का भी नाम लिखा होगा। संबंधित पौधे के नियमित देखरेख के लिए शिक्षकों की ओर से बच्चों व उनकी माता को प्रेरित किया जाएगा। साथ ही सोशल मीडिया व अन्य सचार माध्यमों से इसे प्रचारित-प्रसारित भी किया जाएगा।

राज्य सरकार के अन्य विभाग इसमें सहयोग करेंगे-

राज्य सरकार के वन एवं पर्यावरण विभाग समेत पंचायती राज विभाग इसमें सहयोग करेंगे। पौधों के लिए सभी बीएसए और बीईओ अपने जिले में वन विभाग तथा पंचायती राज विभाग से समन्वयन स्थापित कर कार्यक्रम को बल प्रदान करेंगे। बच्चों का उत्साह और जुड़ाव बना रहे इसके लिए शिक्षक लगातार उन्हें प्रेरित करेंगे।

अन्तर्राष्ट्रीय गणित प्रतियोगिता: 30 देशों के छात्र ले रहे भाग

लखनऊ। सिटी मोन्टेसरी स्कूल गोमती नगर प्रथम कैम्पस द्वारा आयोजित पांच दिवसीय इण्डिया इण्टरनेशनल मैथमेटिक्स कम्पटीशन किया गया। इसका उद्घाटन शनिवार शाम को जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने सीएमएस कानपुर रोड ऑडिटोरियम किया। इस अवसर पर छात्रों ने 30 देशों से पधारे प्रतिभागी छात्रों व गणित विशेषज्ञों के सम्मान में शिक्षात्मक-सांस्कृतिक कार्यक्रमों का अनूठा समां बांधा।फिलीपीन्स के गणितज्ञ डॉ. साइमन एल चुआ, ताईवान के गणितज्ञ प्रो. वेन सेन सुन, बुल्गारिया के गणितज्ञ व्लादिस्लाव मरिनोव आदि की उपस्थिति ने समारोह की गरिमा को बढ़ाया। विदित हो कि इण्डिया आईएमसी का आयोजन 27 से 31 जुलाई तक आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 30 देशों के 1000 से अधिक छात्र प्रतिभाग कर रहे हैं।इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्य अतिथि जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने कहा कि विश्व के बाल गणितज्ञों को एक मंच पर एकत्रित करने का सीएमएस का यह प्रयास अत्यन्त सराहनीय है। इस आयोजन ने छात्रों को स्वर्णिम अवसर प्रदान किया है और मुझे विश्वास है कि यह अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता छात्रों की गणितीय व विश्लेष्णात्मक प्रतिभा को निखारने में अहम भूमिका निभायेगा। प्रो. किंगडन ने कहा कि इस सम्मेलन का उद्देश्य भावी पीढ़ी को मात्र एक कुशल गणितज्ञ बनाना ही नहीं है बल्कि इसके माध्यम से भावी पीढ़ी को अच्छे बुरे की पहचान होगी।

करने वाला एक संवेदनशील विश्व नागरिक बनाना है।

कैंसर के खिलाफ लड़ाई की तेज, शीघ्र जांच और रोकथाम पर जोर दिया

कैंसर से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं पर जल्द जांच पड़ताल और रोकथाम रणनीति की महत्वपूर्ण भूमिका पर जागरूकता फैलाई

बीपीएस न्यूज

कानपुर। कैंसर देखभाल एवं अनुसंधान में अग्रणी संस्थान राजीव गांधी कैंसर इंस्टिट्यूट एंड रिसर्च सेंटर (आरजीसीआईआरसी) ने मेडिकल कम्युनिटी से संवाद स्थापित करते हुए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए), कानपुर के साथ मिलकर आईएमए भवन में एक सतत शिक्षा कार्यक्रम (सीएमई) का आयोजन कर देश पर कैंसर के बढ़ते भार का समाधान करने के प्रयास तेज किए। लांसेट ब्रैस्ट कैंसर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कैंसर के मामलों में बढ़ोतरी की भविष्यवाणी करते हुए वर्ष 2020 के 2.3 मिलियन की तुलना में वर्ष 2040 तक दुनियाभर में 3 मिलियन से ज्यादा कैंसर के मामलों सामने आने का अनुमान लगाया है। युवा महिलाओं में ब्रैस्ट कैंसर के बढ़ते मामलों को देखते हुए विशेषज्ञ जल्द जांच-पड़ताल और उपचार को इस बीमारी के खिलाफ लड़ाई में अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हैं। डॉ. राजीव कुमार, सीनियर कंसलटेंट एंड चीफ ऑफ ब्रेस्ट सर्विसेज, आरजीसीआईआरसी, के अनुसार, ब्रैस्ट कैंसर भारत की महिलाओं में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कैंसर है। जल्द पहचान से ब्रेस्ट कैंसर के ठीक होने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है। बीमारी की जल्द जांच-पडताल वाले मामलों में से लगभग 85-90त्न मामलों में बीमारी ठीक हो जाती हैं। एडवांस स्टेज में भी असरदार दवाईयों, सर्जिकल प्रक्रियाओं, और रेडिएशन थेरेपी से ब्रेस्ट कैंसर मरीजों के पक्ष में परिणाम आने की संभावना रहती है। विशेषज्ञों ने पेंसिटोपेनिया के मामलों की तुरंत जांच-पड़ताल और उन्हें रेफर करने पर भी प्रकाश डाला। पेंसिटोपेनिया एक तरह की बीमारी होती है, जिसमें सभी तरह की रक्त कोशिकाएं या ब्लड सैल्स (लाल कोशिकाएं, सफेद कोशिकाएं और प्लेटलेट्स) कम मात्रा में पाई जाती हैं।पेंसिटोपेनिया के साथ कई तरह के रक्त कैंसर हो सकते हैं। कोशिकाओं की संख्या ज्यादा होने से कैंसर की संभावना को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन कम संख्या होने को गलती से विटामिन की कमी या दूसरे कारण से जोड़ दिया जाता है। लेकिन, पेंसिटोपेनिया से कैंसर कोशिकाओं से ढकी अस्थि-मज्जा (बोन मेरो) की स्थिति बन सकती है, जिससे स्वस्थ कोशिकाओं के निर्माण में रुकावट आती है। इसकी जांच-पड़ताल में देरी घातक साबित हो सकती है, क्योंकि ल्यूकेमेनिया और अप्लास्टिक एनीमिया जैसे परिस्थितियों के लिए जल्द उपचार जरूरी है, क्योंकि इसमें समय से अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण की आवश्यकता होती है।, डॉ. नरेंद्र अग्रवाल, सीनियर कंसलटेंट, डिपार्टमेंट ऑफ हेमाटो-ऑन्कोलॉजी एंड बोन मेरो ट्रांसप्लांट, आरजीसी आईआरसी ने बताया।हानिकारक माना जाता है, और इसके साइड इफेक्ट भी कम होते हैं।

पिकअप व दूध टैंकर में भिड़ंत, चालक की मौके पर मौत

मृतक की फाइल फोटो

बीपीएस न्यूज

कानपुर। कानपुर थाना नौबस्ता के बरकाती मस्जिद निवासी मोहम्मद फैसल पुत्र नफीस रात्रि लगभग 9 बजे पिकअप में मछली का दाना लेकर लखनऊ गया हुआ था। माल उतार कर वापस लौट रहा था कि तभी तड़के सुबह 4 बजे हरदोई संडीला मार्ग पर चालक फैसल को झपकी आ जाने के कारण दूध के टैंकर से भिडंत हो गई। इससे पिकअप चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गयी। शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फैसल छह बहनों के बीच अकेला भाई था। दुघर्टना की खबर से परिवार में कोहराम मच गया। मां और पत्नी का बुरा हाल था । खबर लिखे जाने तक शव का पोस्टमार्टम नहीं हो सका था।

विधायक ने सिंचाई विभाग के एई को बुलडोजर की नोटिस पर लिया आड़े हाथों

कानपुर। सिंचाई विभाग की नहर हलुवाखंडा में है। जो कि गोविन्द नगर विधानसभा के अंतर्गत आती है। नहर के दोनों तरफ लोगों ने अवैध निर्माण कर कच्चे-पक्के मकान बना लिए हैं। सिंचाई विभाग ने शुक्रवार को 40-50 मकानों पर खाली करने के लिए नोटिस चस्पा किए।

स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना क्षेत्रीय विधायक सुरेंद्र मैथानी को दी। विधायक मौके पर पहुंचे। क्षैत्रीय लोगों ने विधायक से नोटिस के बारे में बताया तो विधायक ने सिंचाई विभाग के इंजीनियर को फोन पर बस्ती में नोटिस के संबंध में पूछा तो इंजीनियर ने सरकारी भाषा समझाने का प्रयास किया। उस पर विधायक ने कहा मुझे ये सब न समझाओं बस्ती गिराने बुलडोजर लेकर आए तो नहर में तुमको और बुलडोजर को घुसेड़ दूंगा। तुम्हारा, तुम्हारी कंपनी और बुलडोजर तीनों का मैं स्वागत करूंगा।उन्होंने कहा- तुम्हारा एक आदमी यहां दिखना नहीं चाहिए। अगर दिख गया तो फिर समझ लेना । मेरी बात को रिकॉर्ड कर लो, जब मुझसे निपट लेना, तब तुम बस्ती में आना। मोदी- योगी जी लोगों को घर दे रहे, तुम उजाड़ना चाहते हो। इस पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मनोज सिंह ने कहा दोबारा नोटिस दिया गया है। घरों को दोबारा से मार्क करवाया जाएगा।

गंगा टास्क फोर्स ने विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के उपलक्ष में चलाया जागरूकता अभियान

बीपीएस न्यूज

कानपुर। भारतीय सेना की 137 सी ई टी एफ टी ए बटालियन 39 गोरखा राइफल गंगा टास्क फोर्स ने विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के उपलक्ष में नाना राव घाट,कानपुर मे जागरूकता अभियान चलाया।गंगा टास्क फोर्स के कमान अधिकारी कर्नल अरविंद प्रसाद एस और कानपुर स्थित कंपनी कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल अनूप कुमार ओझा के दिशा निर्देश पर विगत 6 सालों से गंगा स्वच्छता अभियान,पौधा रोपण, घाटों की गश्त, जागरूकता अभियान निरंतर कर रही है। इस अवसर पर गंगा टास्क फोर्स के सूबेदार समरजीत सिंह ने एनसीसी कैडेट्स और गंगा टास्क फोर्स के जवानो ने साथ मिलकर नाना राव घाट पर पौधारोपण और सफाई अभियान चला कर लोगों को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के लिए जागरूक किया और बताया कि विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के प्राकृतिक वातावरण से विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुकेगा जीव-जंतुओं और पेड़ों का संरक्षण करना है। यह दिन वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए पर्यावरण की सुरक्षा में प्रत्येक व्यक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देता है।

बाल्मीकि समाज परंपरागत रूप भाजपा समर्थक

कानपुर। सीसामऊ विधानसभा के उपचुनाव को लेकर बाल्मीकी समाज की महत्वपूर्ण बैठक पार्टी कार्यालय नवीन मार्केट में सम्पन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष दीपू पांडे व संचालन जिला मंत्री धीरज बाल्मिकी ने किया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिला अध्यक्ष दीपू पांडे ने कहा कि सीसामऊ विधानसभा में करीब 28 से 30 बड़ी दलित बस्तियां है जिनमें बहुतायत संख्या में बाल्मीकि भाई निवास करते है विशेष रूप से 9/50 बेनाझाबर 12/480 ग्वालटोली द्वारिकापुरी रायपुरवा चुन्नीगंज गुदड़ बस्ती में हमारे दलित भाई और बाल्मीकि भाई रहते है। बाल्मीकि समाज परंपरा गत रूप से भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करता इसके बावजूद हमारे बाल्मीकि नेता और कार्यकर्ता बस्तियों में पूर्ण रूप से सक्रिय होकर पूर्ण समर्थन और आशीर्वाद प्राप्त करेगा।बैठक में प्रमुख रूप से राजू बाल्मिकी किशन लाल सुदर्शन राजू बाल्मिकी बबुआ बाल्मिकी संजीत कुमार विजय वर्मा शारदा दीन जिला मीडिया प्रभारी

बड़े भाई ने शराबी भाई को बीच सड़क लात-घूसों से पीटा

बीपीएस न्यूज

कानपुर। युवक को बीच सड़क पीटने का मामला सामने आया है। पीटने वाला युवक का बड़ा भाई है। जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें दिख रहा है कि बड़ा भाई छोटे भाई को बाल पकड़कर जमीन में गिराता है। पहले लात से मारता है, फिर तमाचे मारता है। इतना मारा कि युवक के शरीर के पूरे कपड़े निकल गए। वो सिर्फ कच्छा पहने रहा।शनिवार रात को भी शराब पीकर घर आया था। मां सरोजनी देवी के साथ मारपीट गाली-गलौज कर रहा था। इसी बात को लेकर अमित शुक्ला ने अपने छोटे भाई अमन शुक्ला ने पहले घर के भीतर और फिर सड़क पर खींचकर बेरहमी से पीटा। अमन शुक्ला आए दिन मारपीट और बवाल करता है। इसी से आजिज होकर बड़े भाई अमित शुक्ला ने ये कदम उठाया। अमित को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अफसरों की राय के बाद मामले में कार्रवाई की जाएगी।

एसीपी नौबस्ता संजय सिंह ने बताया-वीडियो वायरल होने के बाद मामले की जांच की। तो, पता चला कि ये घटना 332 / क्कराजीव नगर, थाना यशोदा नगर के रहने वाले अमित शुक्ला के घर का है। अमित शुक्ला का छोटा भाई अमन शुक्ला शराब का लती है।

डॉ. वी के साहू को साहू समाज का प्रदेश महामंत्री किया गया नियुक्त

भारतीय तैलिक साहू राठौर महासभा उत्तर प्रदेश की प्रांतीय बैठक गांधी भवन केसरबाग लखनऊ के करन भाई सभागार में हुई संपन्न

बीपीएस न्यूज

कानपुर-लखनऊ। भारतीय तैलिक साहू राठौर महासभा उत्तर प्रदेश की प्रांतीय बैठक गांधी भवन केसरबाग लखनऊ के करन भाई सभागार में आयोजित की गई कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश अध्यक्ष एवं माननीय नगर विकास राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार श्री राकेश राठौर गुरु प्रांतीय बैठक में शामिल हुए वही बैठक में श्री राम नारायण साहू पूर्व सांसद एवं संस्था के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष की गरिमामई उपस्थिति रही और बैठक का संचालन रमाशंकर साहू युवा प्रदेश अध्यक्ष द्वारा किया गया प्रदेश अध्यक्ष राकेश राठौर गुरु माननीय नगर विकास मंत्री द्वारा भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष कानपुर बुंदेलखण्ड क्षेत्र एवं नमो नमो मोर्चा भारत के प्रदेश अध्यक्ष डॉ.वी के साहू जी को एवं मुनेश्वर प्रसाद गुप्ता (भदोही) को प्रदेश का महामंत्री मनोनीत किया गया।

वही श्रीमती अर्चना साहू महिला प्रदेश अध्यक्ष द्वारा संगठन में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश स्तर एवं जिला स्तर पर महिलाओं को विभिन्न पदों पर पद अधिकारी मनोनीत किया गया जिसका विवरण जनक नंदिनी सिद्धार्थ नगर प्रदेश महामंत्री,ललिता राठौर औरैया प्रदेश महामंत्री ,डॉ विद्यावती राठौर लखनऊ प्रदेश कोषाध्यक्ष,शकुंतला साहू एटा प्रदेश उपाध्यक्ष ,मनोरमा गुप्ता बलिया प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष,मंजू गुप्ता गाजियाबाद प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, आराधना गुप्ता चंदौली जिला अध्यक्ष चंदौली, मालती गुप्ता चंदौली प्रदेश उपाध्यक्ष, उमा साहू लखनऊ प्रदेश उपाध्यक्ष, तान्या राठौर नोएडा जिला अध्यक्ष नोएडा आदि लोगों को पदभार दिया गया।कार्यक्रम में डॉक्टर वी.के. साहू प्रदेश महामंत्री जी ने कहा कि तेली साहू राठौर समाज की राजनीतिक भागीदारी लगभग शून्य है और समाज को उसका हक़ नहीं मिल रहा है जब कि उत्तर प्रदेश में तेली समाज की लगभग 2 करोड़ की आबादी है समाज के ज़्यादातर लोग व्यापारी वर्ग से आते हैं और राजनीतिक दलों की तन मन और धन से मदद करते हैं किन्तु तेज़ी समाज को राजनीति में हिस्सेदारी किसी भी दल में नहीं मिलती।डॉक्टर वी के साहू ने कहा अब समय आ गया है कि हम सब पिछड़ा वैश्य को एकजुट होने की जरूरत हैवहीं जन समस्याओं से जुड़े मुद्दों पर ध्यान आकर्षित किया।प्रदेश सरकार के मंत्री श्री राकेश राठौड़ जी ने अपने संबोधन में कहा समाज की समस्याएँ हैं। जिस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा साथ ही सभी को एकजुटता बनाकर समाज को ताक़त प्रदान करने पर ज़ोर दिया।

गांव की सीसी रोड में जलभराव का कौन जिम्मेदार ?

- गांवो के विकास कार्यों में करोडों लाखो का बजट खत्म होने के बाद जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं
- ब्लाक के चक्कर लगाने के बाद अफसर नहीं दे रहे ध्यान
- जिले में संचारी रोग अभियान चल रहा लेकिन फिर भी बुरे हाल

बीपीएस न्यूज

कानपुर देहात। मलासा विकास खंड के ग्राम पंचायत गिरदौ का माजरा नारायणपुर में आरसीसी रोड पर नल निकासी की उचित व्यवस्था न होने से गांव के ग्रामीण और राहगीर परेशान हो रहे हैं । जबकि जिले में अभी भी संचारी रोग अभियान के कुछ दिन बाकी है फिर जिम्मेदार लोग अनजान बने हुए हैं।गांव के ग्रामीण रामनाथ मास्टर, रामअवतार, मन सिंह, रामकिशोर, रामसेवक, मनी राम, तिलक चन्द्र बाबू,आदि और लोग ने बताया है कि पूर्व सचिव दीपक यादव के द्वारा अवगत कराया गया था लेकिन इनके द्वारा भी कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। पिछले डेढ़ साल से जलजमाव की समस्या से जूझ रहे है। आरसीसी रोड के दोनो तरफ नाली निर्माण नहीं होने से ग्रामीण गंदा पानी को पार कर आने जाने को मजबूर है। जिसके विकास के लिए सरकार द्वारा लाखों रुपये दिए गए है। बावजूद एक अदद नाली के ग्रामीण वर्षों से तरस रहे हैं।

ग्रामीणों की मानें तो इस समस्या के समाधान के लिए वे पंचायत के मुखिया से लगातार बीडीओ तक से गुहार लगा चुके है। बावजूद किसी भी स्तर पर उन्हें राहत नहीं मिली है। लिहाजा ग्रामीणों का जीवन मुश्किल से गुजर रहा है। जलजमाव के कारण सबसे अधिक परेशानी गांव की महिलाओं व छोटे बच्चों को हो रहा है। गर्मी के और बरसात के मौसम में बच्चों का स्कूल भी बाधित हो रहा है। ओर मच्छर ग्रामीण और छोटे छोटे बच्चे पर हमला बोल रहे हैं जबकि महिलाओं व बुजुर्गों की दिनचर्या भी जलजमाव से बाधित हो रही है।

बी पी एस न्यूज
हिन्दी साप्ताहिक
मुद्रक प्रकाशक स्वात्वाधिकारी बुद्ध प्रकाश साहू द्वारा मां प्रिन्टर्स गार्डेन नं. 6-ए/7 रेल बाजार कानपुर नगर से मुद्रित एवं 344- बगाही भट्ठा टी.पी. नगर कानपुर से प्रकाशित। आर.एन.आई. नं. UPHIN/ 2016/ 66740, डाक पंजीयन सं. कानपुर सिटी 304/2024-2026, सम्पादक बुद्ध प्रकाश साहू मो.: 8423454502 , व्हाट्सअप 9335908846 email:bps.knp786@gmail.com info@bpsnews.in www.bpsnews.in नोट-समस्त विवादों का न्यायक्षेत्र कानपुर नगर न्यायालय होगा। समाचार पत्र में प्रकाशित समस्त लेखों एवं समाचारों की जिम्मेदारी लेखकों व संवाददाताओं की होगी। कृपया कोई भी आपत्ति हो तो 15 दिनों के अंदर भेजें।